राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका

वर्ष-12, अंक-9, दिसंबर 2025

₹ 20/- पेज-52

राष्ट्र समाज

आपकी आवाज़

मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) में एक परंपरागत ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत और धर्मग्रंथों के विद्वान थे। बालक मदन मोहन ने अपने पारिवारिक संस्कारों से सत्य, अनुशासन और सेवा की भावना पायी।

मदन मोहन मालवीय

शिक्षा, मातृभूमि और आदर्श पत्रकारिता के अमर योद्धा

खुशहाल किसान
उत्तर प्रदेश की पहचान

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत
धान, मक्का, बाजरा एवं ज्वार खरीद
वर्ष 2025-26

प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में सीधे किसानों से धान, मक्का, बाजरा एवं ज्वार खरीद की जा रही है।

इस वर्ष धान, मक्का, बाजरा एवं ज्वार की बिक्री हेतु एकल पंजीकरण की व्यवस्था, खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ वास्तविक किसानों को ही दिलाने हेतु पारदर्शी ऑनलाइन खरीद की व्यवस्था।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

धान (कॉमन) ₹2,369/- प्रति क्विंटल
धान (ग्रेड-ए) ₹2,389/- प्रति क्विंटल
मक्का ₹2,400/- प्रति क्विंटल
बाजरा ₹2,775/- प्रति क्विंटल
ज्वार (हाइब्रिड) ₹3,699/- प्रति क्विंटल
ज्वार (मालदाण्डी) ₹3,749/- प्रति क्विंटल

मक्का खरीद हेतु 25 जनपदों में 117 केंद्र स्थापित

बाजरा खरीद हेतु 33 जनपदों में 279 केंद्र स्थापित

ज्वार खरीद हेतु 11 जनपदों में 78 केंद्र स्थापित

धान खरीद हेतु 4000 क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद का लक्ष्य

किसान भाइयों से अपील

अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने हेतु अपनी फसल की बिक्री राजकीय क्रय केंद्र पर करें और योजना का लाभ उठाएं।

17% तक नमी का धान खरीदा जा सकता है, अतः धान को अच्छी तरह सुखाकर, साफ कर खरीद केंद्र पर लाएं।

किसान भाई अपना आधार कार्ड अद्यतन रखें एवं वर्तमान में उपयोग किए जा रहे मोबाइल नम्बर को ही आधार कार्ड से लिंक कराएं।

1. किसान भाई अपना व्यक्तिगत विवरण/सूचना यथा-भूलेख विवरण/खतौनी, आधार संख्या, मोबाइल नम्बर, कृषक पंजीकरण में प्रयुक्त मोबाइल नम्बर में प्राप्त ओटीपी इत्यादि किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें।

2. किसानों को धान के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाना है। किसान भाई अपनी बैंक शाखा से सम्पर्क कर अपना आधार एन.पी.सी.आई. पोर्टल पर अवश्य मैप करा लें।

3. किसान पंजीकरण में गाटावार विवरण के अनुसार एग्रीस्टैक एवं ई-पड़ताल के डाटा का प्रयोग करके आटोमेटेड सत्यापन की व्यवस्था की गयी है।

कृषक किसी भी सहायता एवं जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 या संबंधित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रमोद तिवारी

महामना की परंपरा और विचारों का उत्सव

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि विचार, संघर्ष और सेवा मिलकर ही राष्ट्र निर्माण की सच्ची राह बनाते हैं। आज जब देश नई चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में उनके सिद्धांतों और आदर्शों को याद करना सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता है।

समाधान फाउंडेशन द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी एवं महामना सम्मान समारोह इसी आवश्यकता को केंद्र में रखकर रची गई एक पहल है, जो विचारों को समाज सेवा से जोड़ने का प्रयास करती है। यह कार्यक्रम २५ दिसंबर २०२५, गुरुवार को दोपहर २ बजे से शाम ५ बजे तक नई दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग में आयोजित किया जाएगा, जहां देश के विभिन्न राज्यों से आए सम्मानित नागरिक एक मंच पर एकत्र होंगे। इस विशेष अवसर पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, उज्जैन के पुजारी महर्षि पंडित रमण गुरु त्रिवेदी का पावन सानिध्य कार्यक्रम को आध्यात्मिक गंभीरता और सांस्कृतिक गरिमा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री श्री संजय सेठ तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में हाथरस (उ.प्र.) के सांसद अनूप प्रधान उपस्थित रहेंगे, जो सार्वजनिक जीवन में सेवा और संवेदनशील नेतृत्व के प्रतीक हैं।

> पंडित मदन मोहन मालवीय जी और भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि विचार, संघर्ष और सेवा मिलकर ही राष्ट्र निर्माण की सच्ची राह बनाते हैं। आज जब देश नई चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है...

समारोह का एक महत्वपूर्ण आयाम महामना सम्मान है,जिसके माध्यम से उन विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा, शिक्षा,संस्कृति, मीडिया, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह सम्मान केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि उस सोच का समर्थन है जो कहती है कि बदलाव केवल नारे से नहीं, निरंतर कर्म से आता है। महामना मालवीय जी और अटल जी के विचार हमें बताते हैं कि राष्ट्र भक्ति का अर्थ केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि अपने दायित्वों को समझकर उन्हें निभाना भी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन मूल्यों—सादगी, संवाद, समावेश और त्याग—को नए सिरे से समझने व समाज में प्रसारित करने का प्रयास किया जाएगा।

यह कार्यक्रम किसी एक संस्था या समूह का नहीं, बल्कि उन सभी जागरूक नागरिकों का उत्सव है जो भारत को विचार व संस्कृति के स्तर पर मजबूत देखना चाहते हैं। समाधान फाउंडेशन सभी पाठकों, युवा साथियों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्यमियों व आम नागरिकों से विनम्र आग्रह करता है कि वे इस विचार गोष्ठी व महामना सम्मान समारोह में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराएं। २५ दिसंबर को समय निकालकर कंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली पहुंचे, महान देश भक्तों को नमन करें, उनके विचार सुनें और अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को सार्थक और सफल बनाएं। आपकी भागीदारी ही इस प्रयास की सबसे बड़ी प्रेरणा है व आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त संदेश भी। यदि चाहें तो अगली स्टेप पर इसी टेक्स्ट का एक छोटा बॉक्स-अप 'अपील' वर्ज़न व एक अलग इवेंट फ्लैश भी तैयार किया जा सकता है, जो आप कवर पेज या इनसाइड पेज पर लगा सकें।

राष्ट्र समाज

वर्ष-12, अंक-09, दिसंबर 2025

RNI No.: DELHIN/2014/56304 ₹20

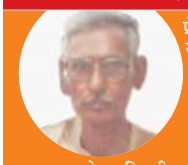

स्व. पुरुषोत्तम तिवारी

प्रेरणा स्रोत

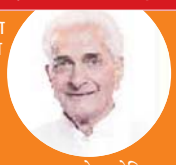

स्व. एन.के. लोहिया

मुख्य संरक्षक
विनीत कुमार गुप्ता

संरक्षक
बालमुकुन्द ओझा, त्रिवेणी नाथ तिवारी,
हरिशंकर दुबे, संजीव गोयल

संपादक
प्रमोद तिवारी

सह संपादक
अवधेश शास्त्री (धर्म समाज)
सुशील ओझा (अर्थ समाज)

सलाहकार मंडल
हरिशचंद्र मिश्रा, अशोक (सकरनी)
ऋषि मित्तल, दिलबाग खंडूजा

ब्यूरो चीफ
पुनीत मिश्रा, अखिलेश शर्मा,
मोहम्मद तैयब खान, अशोक शर्मा,
श्यामल सिन्हा

कानूनी सलाहकार
अधिवक्ता बीपी पाण्डेय, गौरव भारद्वाज

प्रसार
पुनीत मिश्रा
9911882767

विज्ञापन
कृष्ण गोपाल मिश्रा
9899819135

डिजाइन व प्रोडक्शन
एनएम मीडिया सॉल्यूशंस, दिल्ली

संपादकीय कार्यालयः मकान नं. 2, हपली मंजिल, पश्चिम एन्क्लेव, रोहतक रोड, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087

दूरभाषः 011-40105158, 9953772767

ई-मेलः rastrasamaj@gmail.com

स्वत्वाधिकारी अपराइट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक प्रमोद तिवारी द्वारा एस-561, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-2, नई दिल्ली-84 से प्रकाशित तथा मित्तल इण्टरप्राइजेज 2016 गोकुल शाह स्ट्रीट सीता राम बाजार दिल्ली-06 से मुद्रित।

*संपादकः प्रमोद तिवारी

लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित

नोटः पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है, तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय में ही किया जावेगा। राष्ट्र समाज पत्रिका में प्रकाशित सभी पद अवैतनिक हैं। पत्रिका के लिए भेजी गयी सामग्री के प्रकाशन पर पूर्व अनुबंध के बिना कोई भी पारिश्रमिक देने की व्यवस्था नहीं है।

इस बार

12 भारत में पुतिन बदलती दुनिया, अडिग दोस्ती

18 दमघोंटू प्रदूषण और सिमटती ज़िंदगी

22 एक राष्ट्र एक चुनाव

24 आम चुनाव में बिहार की विनिंग टीम के साथ ही उतरेगी बीजेपी

26 हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद चाल से ममता की सत्ता पर मंडराया संकट

36 नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार

38 जमी बर्फ पिघली, दोस्ती की नई शुरूआत

40 सर्दियों में फायदेमंद गुड़, तिल और मूंगफली

28 इंडिगो संकटः आसमान पर बढ़ता एकाधिकार

30 गोवा अग्निकांड : भ्रष्टाचार और लापरवाही की संयुक्त त्रासदी

34 कर्नाटक की सियासत में अब डीके रहेंगे...

42 मुक्ति देने वाली शिक्षा की जरूरत

46 महिला खिलाड़ीः बेमिसाल रोशन लड़कियां

48 दीपिका का ऐसा रोमांस पहले कभी नहीं देखा होगा!

प्रमोद तिवारी

मदन मोहन मालवीय

शिक्षा, मातृभूमि और आदर्श पत्रकारिता के अमर योद्धा

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन, विचारों और कर्मों से राष्ट्र निर्माण की दिशा तय की। इन विभूतियों में पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि एक शिक्षाविद्, पत्रकार, धर्मनिष्ठ राष्ट्रनायक और भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि राष्ट्रसेवा केवल राजनीति नहीं, बल्कि एक साधना है। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) में एक परंपरागत ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत और धर्मग्रंथों के विद्वान थे। बालक मदन मोहन ने अपने पारिवारिक संस्कारों से सत्य, अनुशासन और सेवा की भावना पायी। इलाहाबाद के मिशन स्कूल और फिर म्योर सेंट्रल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाजसेवा की ओर अग्रसर हुए।

राजनीति और राष्ट्रसेवा का मार्ग

मालवीय का सार्वजनिक जीवन 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन से आरंभ हुआ। अपने पहले ही भाषण से उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की लहर पैदा कर दी। उन्होंने जीवनभर राजनीति को नीति और नैतिकता का मार्ग माना। चार बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मालवीय जी ने स्वतंत्रता संघर्ष को धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जोड़ा। वे संयमित भाषा के समर्थक थे -उनके विचार जोश से भरे होते, परंतु उनमें संयम और विवेक का अद्भुत संतुलन होता। उन्होंने नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन और राउंड टेबल सम्मेलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

पत्रकारिता में योगदान

पंडित मालवीय भारतीय पत्रकारिता के प्रथम आदर्शों में से एक थे। उन्होंने 'अभ्युदय', 'लिडर'जैसे पत्रों के माध्यम से स्वतंत्र विचार, जनचेतना और राष्ट्रीय स्वाभिमान को सशक्त किया। मालवीय मानते थे कि 'पत्रकारिता का धर्म राष्ट्र और समाज के प्रति निष्ठा है, न कि सत्ता के प्रति।' उनकी लेखनी में न उग्रता थी, न भय – केवल विवेक, सत्य और संवेदनशीलता थी। वे पत्रकारों से अपेक्षा करते थे कि वे जनता के मार्गदर्शक बनें, भटकाने वाले नहीं। आज जब मीडिया पर व्यावसायिकता का दबाव है, तब मालवीय जी की पत्रकारिता और भी अधिक प्रासंगिक हो उठती है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय: भारत का ज्ञान-तीर्थ

मालवीय जी का सबसे बड़ा योगदान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की स्थापना है। 1916 में स्थापित बीएचयू न केवल एक शिक्षण संस्थान है, बल्कि एक संस्कृतिरक्षक आंदोलन का प्रतीक भी है। मालवीय जी ने स्वयं देश के कोने-कोने से दान एकत्र कर इसे साकार किया। उन्होंने शिक्षा को मात्र रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्रनिर्माण और आत्मनिर्भरता का आधार माना। बीएचयू आज भी उनकी दृष्टि का जीवंत प्रतीक है, जहां ज्ञान के साथ संस्कार का संगम होता है। मालवीय जी गहरे धार्मिक थे, पर उनका धर्म मानवता पर आधारित था। उन्होंने कहा था- 'सच्चा धर्म वही है जो

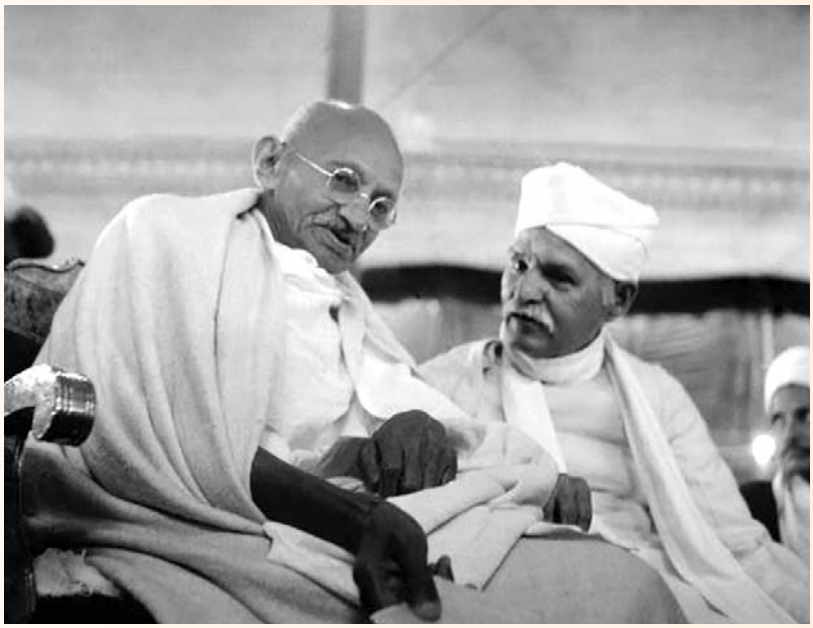

सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं।'उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता और समरस समाज के लिए लगातार प्रयास किए। उन्होंने समाज को अंधविश्वास से ऊपर उठाने, शिक्षा और विज्ञान को अपनाने का संदेश दिया। एक नेता के रूप में मालवीय ने ब्रिटिश सरकार की परिषद में भारतीयों के अधिकारों की आवाज बुलंद की। उन्होंने बाल मजदूरी के विरोध में, उद्योगों के संरक्षण के लिए और भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु ठोस प्रस्ताव रखे। उनकी शैली में विवेकपूर्ण तर्क और नैतिक साहस था।

मालवीय जी के आदर्श और आज का भारत

आज जब शिक्षा व मीडिया दोनों ही क्षेत्र चुनौतियों से घिरे हैं, मालवीय जी के आदर्श हमें सही दिशा दिखाते हैं। उन्होंने सिखाया कि सत्ता से मतभेद हो सकते हैं, पर संस्कार से नहीं। उनके जीवन का संदेश है -'सत्य, सेवा और संस्कार ही राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी हैं।' भारत ने 2014 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर इस महान विभूति की सेवा भावना को नमन किया।

महामना सम्मान: मालवीय की प्रेरणा को नया रूप

मालवीय जी की 164वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष 25 दिसंबर को 'समाधान फाउंडेशन' द्वारा एक विशेष कार्यक्रम 'महामना सम्मान' आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन शिक्षा, समाजसेवा, पत्रकारिता और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह कार्यक्रम न केवल महामना की स्मृति को नमन करेगा, उनकी शिक्षाओं-'चरित्रवान नेतृत्व और नैतिक पत्रकारिता'को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश भी देगा। समाधान फाउंडेशन का यह प्रयास इस बात का प्रतीक है कि मालवीय जी के विचार आज भी जीवंत हैं और समाज को दिशा दे रहे हैं। मदन मोहन मालवीय का जीवन भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है -जहां शिक्षा, संस्कृति, पत्रकारिता और राष्ट्रसेवा एक ही सूत्र में बंधे हैं। वे उन दुर्लभ व्यक्तित्वों में थे जिन्होंने कहा नहीं, किया; जिन्होंने लिखा नहीं, जिया। आज जब हम महामना सम्मान जैसे आयोजनों के माध्यम से उनके आदर्शों को याद करते हैं, तो यह केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक नई प्रतिबद्धता है-देश, समाज और मानवता के प्रति वही निष्ठा, जिसे मालवीय जी ने अपने जीवन से परिभाषित किया था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस लेख का प्रेस रिलीज संस्करण (लगभग 250-300 शब्दों का, 'समाधान फाउंडेशन'केंद्रित प्रारूप में) भी तैयार कर दूं, ताकि उसे मीडिया या निमंत्रण पत्र के लिए उपयोग किया जा सके।

अटल बिहारी वाजपेयी:

राजनीति के कवि और जनभावनाओं के अटल प्रतीक

प्रमोद तिवारी

भारतीय राजनीति के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज है जिन्होंने राजनीति को मानवीय संवेदना और संवाद का स्वर दिया। वे केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि कवि, चिंतक और लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी थे, जिन्होंने शब्दों के माध्यम से दिलों पर राज किया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी संस्कृत के अध्यापक और कवि थे। माता कृष्णा देवी के संस्कारों ने अटल जी को विनम्रता व सत्यनिष्ठा की राह दिखाई। उन्होंने ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की उपाधि ली। बाद में डी.ए.वी. कॉलेज, कानपुर से राजनीति शास्त्र में एम.ए. किया। छात्र जीवन में ही उनमें वक्तृत्व कला व राष्ट्रसेवा के संस्कार गहराई से विकसित हो चुके थे।

स्वतंत्रता आंदोलन और वैचारिक नींव

वाजपेयी जी स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में सक्रिय रहे। वे भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित हुए और ब्रिटिश शासन का विरोध किया। आजादी के बाद उन्होंने लेखन और पत्रकारिता को साधन बनाया। उन्होंने 'राष्ट्रधर्म' ,'पांचजन्य' और 'स्वदेश' जैसे पत्रों से जुड़कर जनता के बीच राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार किया। पत्रकारिता ने उनके सोच और दृष्टिकोण को परिपक्व बनाया। वे मानते थे कि पत्रकारिता केवल खबर नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम है।

जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा

अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा भारतीय जनसंघ से शुरू हुई। उनके गुरु डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन्हें राजनीति की निष्ठा और राष्ट्रहित की अवधारणा दी। मुखर्जी के निधन के बाद वाजपेयी जी ने जनसंघ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी तो अटल जी को विदेश मंत्री बनाया गया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर इतिहास रचा और भारत की पहचान को विश्व मंच पर मजबूती दी। 1980 में जनसंघ से अलग होकर जब भाजपा बनी तो वाजपेयी जी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने संगठन को व्यवहार, सहिष्णुता और संवाद की राजनीति पर खड़ा किया।

संसद में शब्दों की अटल छाप

वाजपेयी जी को भारत के इतिहास के सबसे प्रभावशाली वक्ताओं में गिना जाता है। संसद में जब वे बोलते, तो विरोधी

दल भी मौन होकर सुनते थे। उनके भाषणों में तथ्य और तर्क के साथ संवेदना और सौम्यता का अद्भुत मेल होता था। उनके शब्दों में जितनी शक्ति थी, उतनी ही गरिमा भी। नेहरू जी भी कहा करते थे, 'वाजपेयी जी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।'यह बात बाद में सच साबित हुई।

प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक योगदान

वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने - पहली बार 1996 में, फिर 1998 और अंततः 1999 से 2004 तक पूरा कार्यकाल। 1998 में उनके नेतृत्व में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण ने भारत को विश्व में स्वाभिमान और आत्म बल से भर दिया। उन्होंने कहा था, 'भारत शांति का पुजारी है, पर अपने सम्मान की रक्षा के लिए सक्षम भी।' उनके कार्यकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू हुई जिसने देश के सड़क नेटवर्क को आधुनिक आकार दिया। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, जिसने विकास को गांवों तक पहुंचाया। वे पड़ोसी देशों के साथ शांति की नीति में विश्वास रखते थे। उनकी लाहौर बस यात्रा और पाकिस्तान के साथ संवाद पहल अद्भुत राजनीतिक साहस का उदाहरण थी।

राजनीति में मर्यादा और सहिष्णुता

अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति को शालीनता और सहिष्णुता की भाषा दी। वे आलोचना को स्वीकार करते थे, पर कटुता को नहीं बढ़ाते। उन्होंने कहा था- 'लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, पर मनभेद नहीं होने चाहिए।' उनकी यही भाषा उन्हें सबका प्रिय बनाती थी। वे विपक्ष में रहते हुए भी देशहित के प्रति उतने ही गंभीर रहते जितने सत्ता में।

एक कवि व विचारक के रूप में अटल

राजनीति के साथ-साथ वाजपेयी जी एक

गहरे संवेदनशील कवि थे। उनकी कविताएं जीवन, राष्ट्रभक्ति, प्रेम और संघर्ष का अद्भुत मिश्रण हैं। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां-'हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा...'-उनके व्यक्तित्व की सच्ची झलक हैं। उनकी लेखनी में संघर्ष की आग और करुणा की कोमलता दोनों मिलती हैं। यही कारण है कि जनता उन्हें केवल नेता नहीं, बल्कि 'अटल कवि'के रूप में याद करती है।

सम्मान और भारतीय राजनीति में योगदान

अटल जी को उनके अद्वितीय योगदान के लिए अनेक सम्मान मिले। उन्हें पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, गोविंद वल्लभ पंत सम्मान, और 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे उन कुछ नेताओं में से थे जिनके शब्दों ने लाखों दिलों को छुआ।

अटल विचार गोष्ठी: उनकी स्मृति में प्रेरणा का मंच

इस वर्ष 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के अवसर पर समाधान फाउंडेशन द्वारा उनके नाम पर एक 'अटल विचार गोष्ठी' आयोजित की जा रही है। इस गोष्ठी का उद्देश्य अटल जी के विचारों, आदर्शों और उनके सकारात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण पर चर्चा करना है। कार्यक्रम में पत्रकारिता, शिक्षा, समाजसेवा और जनविकास से जुड़े बुद्धिजीवी, युवा और शोधकर्ता भाग लेंगे। इस गोष्ठी में उनके भाषणों, कविताओं और राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर चर्चा होगी -ताकि नई पीढ़ी यह समझ सके कि राजनीति का अर्थ केवल सत्ता नहीं, बल्कि समाज की सेवा है। **समाधान फाउंडेशन** का यह आयोजन उनके जीवन को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ संवाद और सहिष्णुता की अटल संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास है। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन हमें यह सिखाता है कि आदर्श राजनीति केवल भाषणों में नहीं, बल्कि कर्मों में झलकती है। उन्होंने दिखाया कि संवेदनशीलता और सच्चाई भी सत्ता से बड़ी ताकत हो सकती है। आज जब राजनीति में ध्रुवीकरण और तीखे शब्दों का दौर है, तब वाजपेयी की शैली हमें शालीनता और विवेक की याद दिलाती है। वे सचमुच उस कवि-पुरुष की तरह थे, जिसने देश को शब्द और कर्म दोनों से जोड़ा।

अटल जी की कविता की एक अमर पंक्ति ही उनके जीवन का सार कह देती है -

'अंधकार से मत डरो, सूर्य बनो!'

और सचमुच, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के वही अविनाशी सूर्य हैं - जो आज भी लोगों के दिलों में उजाला फैलाते हैं।

समाधान फाउंडेशन के संस्थापक/अध्यक्ष डॉ . प्रमोद तिवारी ने कहा कि संस्था के माध्यम से समाज के लोगों को सामाजिक न्याय शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सामर्थ अनुसार निःस्वार्थ सेवा प्रदान कर समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने का कार्य रही हैं। ये संस्था जरूरतमंदों को भोजन-कंबल वितरण, रक्तदान शिविर, बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण (पौधरोपण) और आत्मनिर्भरता के लिए कौशल विकास जैसे कार्यों के माध्यम से समाज को सशक्त और सुदृढ़ बनाने में सराहनीय भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग,ड्रेस आदि सामर्थनुसार उपलब्ध कराई जाती है।

समाधान फाउंडेशन के प्रमुख सराहनीय कार्यः

स्वास्थ्य सेवाः निःशुल्क चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर, एम्बुलेंस सेवाएं और गरीब मरीजों को दवा व उपकरणों की सहायता करना।

शिक्षा और बाल विकासः बच्चों के लिए स्कूल, कौशल विकास केंद्र, और शिक्षा सामग्री (स्वेटर, ड्रेस) का वितरण करना।

महिला सशक्तिकरणः महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण, लघु उद्योग को बढ़ावा देना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

आपदा राहतः बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पीड़ित लोगों को भोजन, पानी, कंबल और राहत सामग्री वितरित करना।

पर्यावरण और समाज सुधारः पौधरोपण अभियान, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन और समाज में एकता व सद्भावना को बढ़ावा देना।

निराश्रितों की सहायताः वृद्धाश्रमों, अनाथालयों का संचालन और बेसहारा लोगों को भोजन व वस्त्र प्रदान करना। ये संस्थाएं सामाजिक न्याय, समानता व मानवाधिकारों को बढ़ावा देकर समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाती हैं, जो समाज विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अभिनेता सत्येन्द्र सिंह

भारत में पुतिन
बदलती दुनिया, अडिग दोस्ती

प्रमोद तिवारी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आगमन कोई साधारण कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि यह सात दशकों से चली आ रही अटूट दोस्ती का एक नया और बुलंद ऐलान है। अक्सर कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न दुश्मन, सिर्फ अपने हित सर्वोपरि होते हैं। लेकिन भारत और रूस के रिश्तों ने इस परिभाषा को बदल दिया है। यह संबंध केवल स्वार्थ पर नहीं, बल्कि अटूट भरोसे और आपसी सम्मान पर टिके हैं।

पुतिन की यह यात्रा ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हो रही है, जब अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित नाटो गठबंधन ने रूस पर कड़े आर्थिक और रणनीतिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। भारत ने न केवल कूटनीतिक स्तर पर रूस को सम्मान दिया, बल्कि ऊर्जा और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उसे अपना सबसे विश्वसनीय साथी माना।

यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

और राष्ट्रपति पुतिन की यह मुलाकात महज दो नेताओं का मिलन नहीं है। यह दुनिया को एक कड़ा संदेश है कि वैश्विक राजनीति की दिशा बदल रही है और एक नए युग की शुरूआत हो रही है।

भारत और रूस की मित्रता का इतिहास लगभग 70 वर्षों का है। शीतयुद्ध काल में रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से लेकर पोखरण परमाणु परीक्षणों तक, रूस ने भारत का साथ दिया। आज जब यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक राजनीति को ध्रूवीकृत कर दिया है, अमेरिका ने भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव बनाया, किंतु भारत ने सामरिक स्वायत्तता की नीति को बनाए रखते हुए रूस का साथ निभाया। पश्चिम के प्रतिबंधों के बीच भारत ने भारी मात्रा में रूसी पेट्रोलियम और गैस खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की तथा रूस को आर्थिक सहारा दिया। यह निर्णय महज एक वाणिज्यिक लाभ का मामला नहीं था, बल्कि भारतीय विदेश नीति की स्वयंभूता का प्रदर्शन था। दूसरी ओर, रूस ने भी भारत को कभी निराश नहीं किया। चाहे एस-400 वायु रक्षा प्रणाली हो, टी-90 टैंक हों, ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना हो या पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुयू-57 से जुड़ा सहयोग, भारत की सैन्य क्षमता में रूस का योगदान निर्णायक रहा है। वहीं पाकिस्तान की शत्रुता के खिलाफ भारत के हितों को रूस का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता रहा। हाल ही में दक्षिण एशिया की बदलती सुरक्षा परिस्थितियों में रूस ने भारत की सामरिक चिंता को समझा और ह्यऑपरेशन सिंदूरह्ल जैसे अभियानों में सहयोग की भूमिका निभाई। यह तथ्य भारत-रूस संबंधों की गहराई और विश्वास को दशार्ता है।

पुतिन और मोदी की वार्ता ऐसे समय आयोजित हो रही है, जब वैश्विक शक्ति-संतुलन परिवर्तन के दौर में है। अमेरिका-चीन तनाव, यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंध, ऊर्जा बाजारों की अस्थिरता और पश्चिमी देशों की रूस के विरुद्ध एकजुटता, इन परिस्थितियों में भारत की भूमिका मध्यस्थ, संतुलक तथा स्वतंत्र धुरी के रूप में उभर रही है। पुतिन भारत को न केवल रक्षा सहयोगी मानते हैं, बल्कि एशियाई भू-राजनीति में संतुलन का स्तंभ भी। वहीं मोदी की विदेश नीति बहुध्रूवीय विश्व की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें रूस का स्थान केंद्रीय है। इस यात्रा से ऊर्जा सहयोग और बढ़ेगा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और रूस उसके लिए सस्ता, विश्वसनीय तथा दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ता। प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने भारत को कच्चे तेल के साथ ही कोयला, गैस व परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग दिया। भारत को सस्ती ऊर्जा देने के पीछे केवल व्यावसायिक हित नहीं बल्कि मित्रता और सामरिक साझेदारी भी निहित है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग और विस्तृत होने की उम्मीद है। भारत का लक्ष्य 'मेक इन इंडिया' रक्षा उत्पादन है और रूस इसके लिए सबसे बड़ा भागीदार बना हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल, राइफल निर्माण, स्पेयर पार्ट सप्लाई और संयुक्त विकास कार्यक्रमों के नए विकल्प वार्ता में उभरेंगे। रूस भारत को केवल उपभोक्ता नहीं, निमार्ता के रूप में स्थापित करने में सहभागी है, जो संबंधों की परिपक्वता को दशार्ता है।

भारत-रूस दोस्ती अब एक नया अध्याय लिखने को तत्पर है। दोनों देशों की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, यहां तक की अमेरिका के साथ बेहतर हुए संबंधों के दौर में भी रूस

हमारा विश्वस्त साझीदार बना रहा है, प्रगाढ़ दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से दोनों देशों की दोस्ती में नई गरमाहट की संभावना के साथ दोस्ती के नये स्वस्तिक उकेरने की बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के वर्षों में अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, लेकिन रूस के साथ देश के दशकों पुराने रक्षा संबंध भी बरकरार हैं। भारत ने अमेरिका और यूरोप से हथियारों की खरीद बढ़ाकर रूस पर निर्भरता को संतुलित बनाया है, लेकिन मॉस्को अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। रूस दोस्ती की ओर आगे बढ़ते हुए भारत के लोगों को रोजगार देने के लिये भी एक समझौता मसौदा तैयार किया है। रूस अपने उद्योगों के लिए 10 लाख भारतीय कुशल श्रमिकों को काम पर रखना चाहता है।

भारत-रूस संबंधों का सबसे मजबूत आधार है-कूटनीतिक विश्वास और सम्मान। रूस ने कभी भारतीय आंतरिक राजनीति या नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। उसने कश्मीर, परमाणु नीति, रणनीतिक साझेदारी और पड़ोसी विवादों पर भारत की संप्रभुता का समर्थन किया। वहीं भारत ने भी रूस की सुरक्षा चिंताओं को समझाकृचाहे नाटो विस्तार का मुद्दा हो या यूक्रेन का संघर्ष। इसलिए भारत ने पश्चिमी दबावों की उपेक्षा करते हुए संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी रूस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में रूस सहयोगी रहा है और भविष्य की यात्री-वाहक मिशनों में भी सहयोग की संभावनाएँ हैं।

दोनों देशों की सांस्कृतिक साझेदारी भी विशेष हैरू योग, आयुर्वेद, साहित्य, रूसी नाट्यकला और भारतीय कलाकृसबने एक-दूसरे समाज में स्थान पाया। फिर भी यह संबंध चुनौतियों से खाली नहीं। चीन-रूस साझेदारी और भारत-अमेरिका निकटता के बीच संतुलन बनाए रखना दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है। रूस चाहता है कि एशिया में भारत संतुलक भूमिका निभाए, वहीं भारत नहीं चाहता कि रूस का झुकाव चीन की ओर अत्यधिक बढ़े। इसी प्रकार रक्षा सहयोग में तकनीक हस्तांतरण, उत्पादन विलंब और आर्थिक भुगतान व्यवस्थाओं पर भी मतभेद रहे हैं। किंतु इन मतभेदों को वार्ता द्वारा

समाधान के प्रयास दोनों राष्ट्रों की परिपक्वता को दशार्ते हैं।

पुतिन की इस यात्रा का महत्व इसलिए भी है कि यह बताती है कि भारत किसी वैश्विक शक्ति के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर संबंध तय करता है। ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा आत्मनिर्भरता, बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था और एशियाई सामरिक संतुलन की दृष्टि से भारत-रूस साझेदारी अपरिहार्य है। मोदी और पुतिन की मुलाकात इस विश्वास की प्रमाणिकता है कि संबंध केवल शीत युद्ध की स्मृतियों पर नहीं, बल्कि समकालीन हितों और भविष्य की रणनीति पर आधारित हैं। यह यात्रा एक प्रतीक है-स्वतंत्र विदेश नीति, सामरिक साझेदारी और सांस्कृतिक सम्मान की। भारत-रूस संबंध केवल दो राष्ट्रों की निकटता का परिचय नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक विशिष्ट वैकल्पिक शक्ति संरचना का निर्माण है। पश्चिमी देशों की आलोचना और प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस ने अपने संबंधों को न केवल जीवित रखा बल्कि सुदृढ़ किया।

इस मुलाकात से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई गति मिलेगी, रक्षा उत्पादन को स्वदेशीकरण का बल मिलेगा, व्यापार एवं तकनीकी सहयोग विस्तृत होगा और रणनीतिक विश्वास की डोर और मजबूत होगी। पुतिन और मोदी की यह वार्ता बताती है कि भूराजनीति केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि भरोसे और सहयोग पर भी टिकती है। अतः कहा जा सकता है कि पुतिन की भारत यात्रा एक नई ऊर्जा, नए दृष्टिकोण और नई साझेदारियों की शुरूआत है-जहाँ भारत और रूस न केवल मित्र हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर संतुलित, स्वाधीन और बहुध्रूवीय विश्व व्यवस्था के निमार्ता भी हैं। यह यात्रा उसी निर्माण का नवीन अध्याय है, जिसमें पुराने भरोसे से जन्म ले रहा है एक नया भविष्य।

एशियाई सद्भाव और पुतिन

पुतिन की यात्रा के बाद एक ठोस शांति पहल होनी चाहिए। भारत, चीन और रूस मिलकर एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पाकिस्तान, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार होने के बावजूद, एक मजबूत सैन्य छाया के तहत काम करना जारी रखे हुए है। फिर भी, उसे एक रचनात्मक संवाद में शामिल होने के लिए

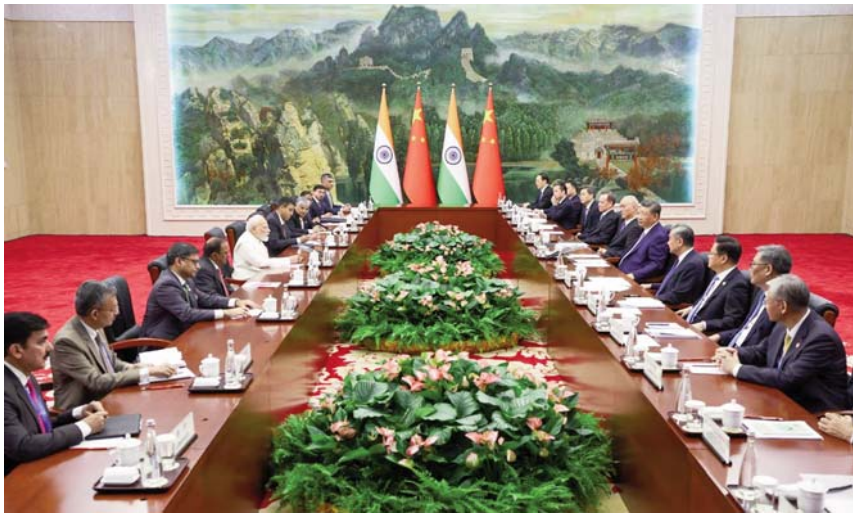

प्रोत्साहित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। भारत को राजनयिक जुड़ाव से पीछे नहीं हटना चाहिए, और सार्क को पुनर्जीवित करने की इच्छा दिखानी चाहिए। केवल संवाद के माध्यम से ही दक्षिण एशिया स्थायी शांति की ओर बढ़ सकता है।

रूस ने दिसंबर 1998 में तत्कालीन प्रधान मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव के माध्यम से रूस-भारत-चीन (आरआईसी) रणनीतिक त्रिकोण का प्रस्ताव रखा था, जिसकी कल्पना अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभुत्व के प्रतिकार के रूप में की गई थी। उस समय भारत ने सीमित उत्साह दिखाया था। हालांकि, बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण ब्रिक्स का उदय हुआ। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन के लिए ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था ताकि चारों देशों की गतिशीलता में वृद्धि को दिखाया जा सके, जो बाद में ब्रिक्स समूह के रूप में एक वैश्विक राजनीतिक पहल के रूप में विकसित हुआ, जिसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना और संतुलित करना है। कोई भी भारतीय सरकार- चाहे उसका राजनीतिक झुकाव जो भी हो- को यह पहचानना चाहिए कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए एक व्यापक सोच और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राष्ट्रपति पुतिन के चीन के साथ करीबी संबंध और पाकिस्तान के साथ उनका व्यावहारिक, गैर-विरोधी जुड़ाव दक्षिण एशियाई पड़ोस में ज्यादा शांतिपूर्ण माहौल के लिए अवसर बनाने में मदद कर सकता है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

गौरी कश्यप

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश कांत 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 14 महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे और फरवरी 2027 में सेवानिवृत्त होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कौन हैं?

सूर्यकांत ने रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की और 1985 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। समय के साथ, उन्होंने हरियाणा के एडवोकेट जनरल के रूप में कार्य किया और 2001 में, 39 वर्ष की आयु में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया।

2004 में, उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बाद में, 3 अक्टूबर 2018 को वे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। इस कदम से कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि न्यायमूर्ति एके गोयल ने कथित तौर पर कॉलेजियम के निर्णय से असहमति जताई थी। इसके बावजूद, कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों से संतुलित प्रतिनिधित्व के महत्व का हवाला देते हुए अपनी नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखी।

2019 में, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया, और कॉलेजियम ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी नियुक्ति यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि सभी उच्च न्यायालयों का उच्चतम स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं?

मुख्य न्यायाधीश कांत ने खुले तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या कोस्वीकार किया है और बताया है कि 90,000 से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने माना कि लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के कारण जटिल हैं, जिनमें सूची में कमियों से लेकर प्रणालीगत गंभीर समस्याएं शामिल हैं।

उन्होंने लंबे समय से अटके मामलों, विशेषकर निचली अदालतों में लंबित उन मामलों को निपटाने में सक्रिय भूमिका निभाने का वादा किया, जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, 'मैं उन मामलों को ढूंढूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि पीठों का गठन हो और उन पर फैसला हो।

मुख्य न्यायाधीश कांत ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर मामलों की बढ़ती संख्या के मुद्दे पर भी ध्यान दिलाया। जैसा कि उनके पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने भी कहा था, लंबित मामलों की संख्या के हमारे आकलन के अनुसार, पिछले छह महीनों में दायर मामलों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है—जो प्रति माह लगभग 4000-5000 मामलों से बढ़कर 7000 से अधिक हो गई है। मुख्य न्यायाधीश कांत ने उच्च न्यायालयों को दरकिनार करते हुए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने वाले वादियों की बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान दिया। शपथ ग्रहण से कुछ दिन पहले पत्रकारों के साथ एक अनौपचारिक बैठक में उन्होंने कहा कि वे इस प्रवृत्ति के कारणों की जांच करना चाहते हैं और जिला न्यायपालिका में विश्वास बहाल करना चाहते हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, मुख्य न्यायाधीश कांत ने निर्णय लेने में देरी करने वाले महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों को हल करने हेतु संविधान पीठों के गठन को प्राथमिकता देने की योजना बनाई है। मध्यस्थता की शक्ति में भी उनका गहरा विश्वास है: इसे ₹सबसे आसान समाधानों में से एक जो निर्णायक साबित हो सकता है₹ बताते हुए, उन्होंने अदालतों और सरकारी निकायों से इसे और अधिक व्यापक रूप से अपनाने की इच्छा व्यक्त की।

दमघोंटू प्रदूषण और सिमटती ज़िंदगी

सुनील कुमार महला

सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही दिल्ली की आबोहवा इन दिनों बुरी तरह बिगड़ गई है। दिल्ली तो दिल्ली,इन दिनों उत्तर भारत के पंजाब , हरियाणा,यूपी के कई शहरों में तो सांस लेना भी दूभर हो गया है और मास्क अब मजबूरी हो चुके हैं।मतलब यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और उत्तर भारत में इन दिनों बेहिसाब प्रदूषण है। गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में 15 दिसंबर 2025 सोमवार को जहरीले स्मॉग की परत छाई रही। एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली के 40 में से 27 निगरानी केंद्रों पर हवा 'सीवियर' कैटेगरी में दर्ज की गई। वजीरपुर में एक्यूआइ 500 तक पहुंच गया, जो अधिकतम सीमा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सीपीसीबी के मुताबिक 500 से ऊपर एक्यूआइ दर्ज नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, घनी धुंध के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित रहा।

दिल्ली एयरपोर्ट से कई एयरलाइंस ने

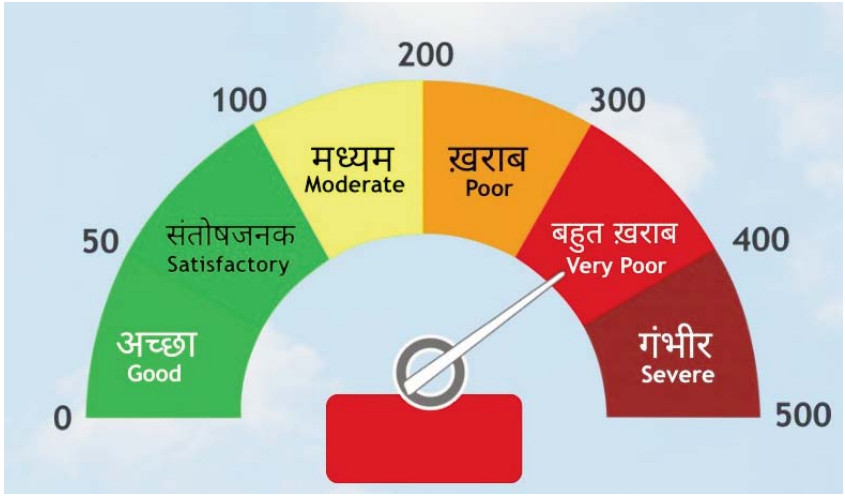

228 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं और 5 को दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया तथा 250 देरी से चलीं। और तो और, भारत आए अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी खराब मौसम के चलते पीएम नरेंद्र मोदी से नहीं मिल सके। उपलब्ध जानकारी अनुसार मेसी की मुंबई से दिल्ली आने वाली चार्टर्ड फ्लाइट ने कोहरे की वजह से देरी से उड़ान भरी। वहीं, पीएम एक घंटे की देरी से तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुए। गौरतलब है कि मेसी की पीएम मोदी से सुबह के वक्त मुलाकात तय थी। इस बीच, प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कक्षा 5वीं तक क्लासेस केवल ऑनलाइन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों और पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाइब्रिड मोड के जरिए पेश होने की सलाह दी है। पाठकों को बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर आने वाले 17 दिसंबर को

सुनवाई करेगा। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि प्रदूषण का असर लोगों के स्वास्थ्य व जीवन प्रत्याशा पर भी पड़ रहा है।

इस क्रम में हाल ही में आरबीआई की आई एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार वर्षों में दिल्ली में लोगों की औसत आयु 1.7 साल कम हो गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि महिलाओं से ज्यादा पुरूषों की उम्र घटी है। बढ़ता प्रदूषण,जल और बदलती जीवनशैली इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। हालांकि, कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सुधरी जीवनशैली के कारण जीवन प्रत्याशा में बढ़ोत्तरी भी हुई है।

गौरतलब है कि यूपी में औसत आयु सबसे अधिक बढ़ी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के लोगों की औसत आयु 65.6 वर्ष से बढ़कर 68.0 वर्ष हो गई है तथा यह पूरे देश में सबसे अधिक है। केरल में औसत आयु सबसे अधिक 75.1 वर्ष है,जो कि बेहतर है। वैसे यदि हम यहां पर राज्यवार औसत उम्र की बात करें तो दिल्ली में यह 74.2 वर्ष, उत्तराखंड में 71.3 वर्ष, पंजाब में 70.8 वर्ष, झारखंड में 69.5 वर्ष, बिहार में 69.3 वर्ष, हरियाणा में 68.8 वर्ष तथा तथा उत्तर प्रदेश में 68.0 वर्ष है। बहरहाल, यह बहुत ही चिंताजनक है कि आज उतर भारत विशेषकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हवा, भोजन, पानी व मिट्टी प्रदूषित हो गई है और शायद यही कारण भी है कि हवा और पानी में कैंसर कारक तत्व तक मिले हैं। कुल मिलाकर प्रदूषण जीवन प्रत्याशा लगातार कम कर रहा है।

पाठकों को बताता चलूं कि हाल में केंद्रीय बैंक ने सांख्यिकी पुस्तिका 2024-25 में औसत आयु से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। जैसा कि एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक ने लिखा है कि 'रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-19 के मुकाबले 2019-23 में दिल्ली में 1.7 साल और पंजाब में दो साल औसत आयु कम हुई। वहीं, हरियाणा में औसत उम्र 1.1 वर्ष कम हो गई। इस तरह, औसत आयु में गिरावट के मामले में पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली है। हालांकि, इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर औसत आयु 0.6 साल बढ़ गई है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत आयु 70.3 वर्ष की है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि हाल ही में जारी शिकागो विश्वविद्यालय की 2025 की रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया है कि भारत में वायु प्रदूषण से औसत उम्र 3.5 साल तक घट रही है और अधिकांश आबादी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से ज्यादा प्रदूषित हवा में रहती है। इससे हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियां, कैंसर का खतरा बढ़ता है। प्रदूषण कम हो तो जीवन प्रत्याशा बढ़ सकती है, खासकर दिल्ली जैसे शहरों में जो जहरीली हवा से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बहरहाल, इस समय राजधानी घने कोहरे की चादर में लिपटी नजर आ रही है।

जहरीली हवाओं से लोग बेहाल हैं और उनमें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं लगातार पैदा हो रही हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पराली (फसल अवशेष) कटने या जलाने का मुख्य समय भी अक्टूबर के अंत से नवंबर के बीच होता है, तथा कभी कभी यह दिसंबर तक भी पहुंच जाता है, खासकर धान (चावल) की कटाई के बाद और गेहूं की बुवाई से पहले, ताकि खेत अगली फसल के लिए तैयार हो सके। वास्तव में यह समय उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बनता है इन दिनों जबकि दिसंबर का महीना चल रहा है, दिल्ली में धूल और धुएं से बनी घनी धुंध ने राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में हालात बेहद खराब कर दिए हैं। दृश्यता भी इतनी कम हो गई है कि सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं, और कम दृश्यता के कारण एक्सीडेंट की घटनाएं भी जन्म ले रहीं हैं।

प्रदूषण और कोहरे की वजह से अकेले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 30 से ज्यादा वाहन टकरा चुके हैं और कई लोगों की मौत हुई है। गौरतलब है कि प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक बार फिर बाहरी खेल गतिविधियां (आउटर स्पोर्ट्स एक्टीवीटीज) तक बंद करने का आदेश देना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने की बात कह चुका था, फिर भी उन्हें जारी रखा गया। इससे साफ होता है कि नियमों और अदालत के निदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। क्या यह विडंबना नहीं है कि आज सरकारें केवल तात्कालिक घोषणाएं तो कर रही हैं, लेकिन प्रदूषण से निपटने के लिए कोई ठोस और दीर्घकालिक समाधान नहीं निकाल पा रही हैं। सच तो यह है कि जो कदम अभी तक उठाए गए हैं, वे अधिक प्रभावी व कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं और इसका नतीजा यह कि दिल्ली वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) लगातार बिगड़ता जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली व एनसीआर में आज प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर हो चुकी है, लेकिन इसके असली कारणों की न तो ईमानदारी से पहचान हो रही है और न ही यह साफ है कि हालात कब सुधरेंगे।

यह काबिले-तारीफ है कि सरकार ने ट्रकों की आवाजाही रोकने, निर्माण कार्य बंद करने और ग्रेप-4 जैसी सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। यह ठीक है कि सरकार अपने स्तर पर सावधानी बरतने की सलाह भी दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत में सिंगापुर उच्चायोग ने भी दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले अपने नागरिकों को भी संभलकर रहने की सलाह दी है, लेकिन फिर भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा, यह चिंताजनक बात है। इससे सवाल उठता है कि जब उपाय मौजूद हैं, तब नतीजे क्यों नहीं दिख रहे ?इसका सीधा अर्थ यह है कि या तो कारणों को सही ढंग से समझा नहीं गया है, या फिर उन्हें दूर करने में प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक संकोच आड़े आ रहे हैं। अब केवल पाबंदियां लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार विभागों की जवाबदेही तय कर ठोस और प्रभावी कार्रवाई करना जरूरी है। वैसे भी प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही नहीं है, वास्तव में यह हम सभी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। प्रदूषण को कम करना किसी व्यक्ति विशेष व सरकार का ही नहीं बल्कि हम सभी का सामूहिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है। अंत में यही कहूंगा कि इन दिनों पूरी दिल्ली लगातार जहरीली हवा की चपेट में है।

'हम है भारत के लोग'...

सुनील कुमार महला

ये भारत के संविधान की प्रस्तावना के आरंभिक शब्द हैं। संविधान और लोकतंत्र देश के नागरिकों को ही संबोधित है। संविधान सभा की बैठकों में संविधान के प्रावधानों और अनुच्छेदों पर व्यापक विमर्श किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी। भारत को स्वतंत्रता मिलना तय हो चुका था। राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जा चुका था, लेकिन विधिवत रूप से भारत का संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बनना तब शेष था। उस दौर में हमारे पुरखों ने संविधान पर विमर्श किया। देश की आजादी के बाद भी संविधान सभा की बैठकें जारी रहीं और अंतिम सदस्य-संख्या 299 थी। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा उनसे पहले सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अंततः 26 नवंबर, 1949 को संविधान को स्वीकृति दी गई और उसे ग्रहण किया गया। हालांकि संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया, लिहाजा उस दिन देश 'गणतंत्र दिवस' मनाता है। कांग्रेस ने देश पर 55 साल से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन कभी 'संविधान दिवस' नहीं मनाया। यह शुरूआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में कराई और उसके बाद देश 26 नवंबर को नियमित तौर से 'संविधान दिवस' मनाता आ रहा है। बीती 26 नवंबर को पुराने संसद भवन के 'सेंट्रल हॉल' (अब संविधान सदन) में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की प्रस्तावना 'हम भारत के लोग' का पाठ किया।

उसी के साथ उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष समेत सभी सांसदों ने यह पाठ दोहरा कर प्रतिज्ञा ली, शपथ ली कि वे संविधान के प्रति प्रतिबद्ध और जवाबदेह रहेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संविधान देश की पहचान का मूल आधार है। यह औपनिवेशिक सोच को छोड़ कर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाने का मार्गदर्शक दस्तावेज है। यकीनन हमारा संविधान देश के औसत नागरिक से लेकर न्यायपालिका, संसद, सरकार तक सभी अंगों का प्राण है। उनकी दिशा और न्याय है। देश की व्यवस्था संविधान से ही संचालित है। देश की संवैधानिक संस्थाएं भी संविधान की परिधि में हैं।

संविधान में आम नागरिक के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो बुनियादी और जीवंत लोकतंत्र के प्रतीक हैं। कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल संविधान को खंडित करने या उसके स्थान पर 'मनु स्मृति' के प्रावधानों को लागू करने के आरोप लगाते रहे हैं। यह राजनीतिक और चुनावी नेरेटिव हो सकता है, जबकि यथार्थ यह है कि 'मनु स्मृति' कोई दस्तावेजी और स्वीकृत संकलन ही नहीं है। वह संविधान का विकल्प कैसे बनाया जा सकता है? भाजपा-आरएसएस को इतना असंवैधानिक और निरंकुश कौन होने देगा? संविधान पर घातक प्रहार, आघात तब किया गया था, जब 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। निश्चित तौर पर वह कालिमा का दौर था। बिना अपराध के नेताओं, पत्रकारों, कलाकारों, कवियों, समाजसेवियों आदि को जेलों में ठूंस दिया गया था।

बहरहाल हम आज उस दौर को भी भूल जाना चाहते हैं, लेकिन देश को यह खुलासा करना चाहते हैं कि संविधान के 39वें और 42वें अनुच्छेद में ऐसे संशोधन किए गए, जिनसे देश तानाशाही की ओर जा सकता था! संशोधन किया गया किराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर के चुनाव संबंधी विवाद अदालत के दायरे से बाहर होंगे। प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त करने की कोशिश की गई। आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी। संविधान की प्रस्तावना में दो नए शब्द जोड़ दिए गए-सेक्युलर और सोशलिस्ट। ये शब्द आज भी मौजूद हैं। अलबत्ता जो एकाधिकारवादी संशोधन थे, उन्हें बाद की जनता पार्टी सरकार के दौरान पुनः संशोधित कर सुधारा गया। इस तरह संविधान बच सका।

Haldiram's
Banao
CHATPATE
PAL AUR
MEETHI
YAADEIN!
Pictures & presentation may not represent the actual product/portion.
Shop Online@www.haldiramsonline.com

1 राष्ट्र चुनाव

अश्विनी उपाध्याय

अधिवक्ता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय

1983 में चुनाव आयोग ने टिप्पणी की थी कि 'अब वह समय आ गया है जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।ह इसी प्रकार, 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था, ₹हमें उस स्थिति में वापस लौटना होगा जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। 2015 में, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 'लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता' पर अपनी रिपोर्ट में 'एक साथ चुनाव कराने की एक वैकल्पिक और व्यावहारिक विधि' की सिफारिश की थी, जिसमें दो चरणों में चुनाव होंगे-कुछ विधानसभाओं के लिए वर्तमान लोकसभा कार्यकाल के मध्य में नवंबर 2016 में और शेष विधानसभाओं के लिए अंत में जून 2019 में। उन सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव, जिनका कार्यकाल निर्धारित चुनाव तिथि से छह महीने से एक वर्ष के भीतर समाप्त होता है, एक साथ कराए जा सकते हैं।

1951-52,1957,1962 और 1967 में एक साथ चुनाव हुए थे। हालांकि, विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने से यह चक्र बाधित हुआ और 1970 में लोकसभा को भी समय से पहले भंग कर दिया गया। यदि भारत अपने विकास एजेंडे में अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, तो बार-बार होने वाले चुनावों से राहत उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1977 से चुनावी खर्च लगातार बढ़ता रहा है। 1971 में यह 11.5 करोड़ रुपये से बढ़कर दोगुना होकर 23 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। 1980 तक यह बढ़कर 54 करोड़ रुपये हो गया। 1989 में यह खर्च 154 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 1977 के स्तर से तिगुना था। महज दो साल बाद, खर्च बढ़कर 359 करोड़ रुपये हो गया। 1996 तक यह आंकड़ा 600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, और 1999 में चुनाव आयोग ने 880 करोड़ रुपये खर्च किए। 2004 में यह राशि फिर से बढ़कर 1,300 करोड़ रुपये हो गई। अस्थायी अनुमानों के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनावों के संचालन पर लगभग 4,500 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि अनौपचारिक अनुमानों के अनुसार, इन्हीं चुनावों पर 30,000 करोड़ रुपये अघोषित रूप से खर्च किए गए। चुनावों की आवृत्ति कम करने से इन बढ़ती लागतों में काफी कमी आ सकती है।

चुनाव दिवस से तात्पर्य चुनाव के लिए निर्धारित दिन से है। कई देशों में, अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए

चुनाव रविवार को आयोजित किए जाते हैं। अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोलीविया, ब्राजील, बुल्गारिया, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, साइप्रस, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, जापान, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूक्रेन और वेनेजुएला जैसे देश इस प्रथा का पालन करते हैं।

दक्षिण अफ्रीका में, राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हर पांच साल में एक साथ होते हैं, जबकि नगरपालिका चुनाव दो साल बाद एक निश्चित तिथि पर होते हैं। स्वीडन में, राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों और स्थानीय निकायों /नगर सभाओं के चुनाव हर चार साल में सितंबर के दूसरे रविवार को एक निश्चित तिथि पर होते हैं।

भारत में, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं , पंचायतों और नगर निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता पर दशकों से बहस चल रही है। चुनावों के लगातार महंगे होते जाने के कारण, भारत के विधि आयोग ने चुनावी कानूनों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट (1999) में शासन में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी।

भारतीय संविधान भारत को 'राज्यों का संघ' बताता है और राज्यों को अपनी सरकारों पर नियंत्रण प्रदान करता है, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। संविधान संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए हर पांच साल में चुनाव अनिवार्य करता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करता कि चुनाव एक साथ होने चाहिए या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में कहा है कि जब चुनावी कानून मौन हों, तो चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत आवश्यकतानुसार कार्रवाई करने की अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं।

लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराने के कई फायदे हैं। इससे चुनाव कराने में लगने वाला समय और खर्च कम होगा, जिसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी, मतदान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और मतदाता पर्चियां शामिल हैं। राजनीतिक दलों

के चुनाव प्रचार खर्च में भी कमी आएगी। इसके अलावा, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है, जिससे आवश्यक शासन संबंधी मुद्दों से ध्यान भटक जाता है।

बार-बार होने वाले चुनाव शासन व्यवस्था में बाधा डालते हैं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता सरकार को ऐसे नीतिगत निर्णयों की घोषणा करने से रोकती है जिन्हें मतदाताओं को प्रभावित करने वाला माना जा सकता है। राजनीतिक अभियान ध्यान भटकाने वाले हो सकते हैं, और चुनाव परिणामों को अक्सर केंद्र सरकार पर जनमत संग्रह के रूप में गलत समझा जाता है, भले ही चुनावों में राज्य-विशिष्ट मुद्दे हावी हों।

2013 से 2018 के बीच, देश भर में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। 2013 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और कर्नाटक में चुनाव हुए। 2014 में लोकसभा चुनावों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा और सिक्किम में भी राज्य चुनाव हुए। 2015 में दिल्ली और बिहार में चुनाव हुए, इसके बाद 2016 में असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव हुए। 2017 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात में चुनाव हुए, जबकि 2018 में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और कर्नाटक में चुनाव हुए।

यदि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की संबंधित सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करती हैं, तो इन राज्यों में चुनाव 2019 के आम चुनावों के साथ ही कराए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम जैसे राज्यों में 2019 के आम चुनावों से छह महीने पहले चुनाव होने की संभावना है, जबकि झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव छह महीने बाद हो सकते हैं। यदि राजनीतिक सहमति बन जाती है, तो इन राज्यों में विधानसभा चुनावों को आम चुनावों के साथ संरेखित करने के लिए छह महीने के लिए स्थगित या आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे एक साथ चुनाव संभव हो सकेंगे। चुनावों को एक साथ कराने से चुनावी गतिरोध की समस्या का भी समाधान होगा, जो लगातार चुनावों के चक्र के कारण सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति है। यह समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जो अपनी-अपनी पार्टियों के प्रमुख प्रचारक होते हैं, अक्सर चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। सभी चुनावों को एक साथ कराने से 58 महीने का स्थिर शासन काल मिलेगा, जिससे सरकारें सुधारों और विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। यह विस्तारित, निर्बाध अवधि नीति निमार्ताओं के लिए दीर्घकालिक सुधारों को लागू करना आसान बनाएगी, प्रशासनिक देरी को कम करेगी और देश के समग्र विकास को लाभ पहुंचाएगी।

आम चुनाव में बिहार की विनिंग टीम के साथ ही उतरेगी बीजेपी

संजय सक्सेना

भारतीय जनता पार्टी बिहार में भले ही नंबर एक की पार्टी उभरी हो, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी जतना दल युनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को ही वह वायदे के अनुसार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रही है तो इसके पीछे तमाम किंतु-परंतु हैं। दरअसल, नीतीश के साथ सरकार बनाते समय बीजेपे इस लिये कोई नया प्रयोग नहीं करेगी क्योंकि उसकी नजर 2029 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। बिहार में सत्ता समीकरण को लेकर पार्टी का रुख यह बताता है कि वह यहां किसी बड़े प्रयोग से बचना चाहती है और स्थिरता पर जोर दे रही है। पिछली सरकार के दौर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के दो उपमुख्यमंत्रियों के संतुलन ने गठबंधन को कार्यात्मक बनाए रखा था। अब जब विधानसभा में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, तब भी आलाकमान का यही फैसला कि वही पुरानी टीम बनी रहेगी, एक सोची-समझी रणनीति का परिणाम है।

> बिहार के मतदाता प्रयोगों से ज्यादा परिणाम देखना चाहते हैं। एक स्थिर सरकार को वे पसंद करते हैं, जो काम में निरंतरता दिखाए। आलाकमान यह समझता है कि बिहार में जो संतुलन नीतीश-बीजेपी के बीच तैयार हुआ है, 2029 तक राजनीतिक जमीन तैयार की जा सकती है।

बीजेपी समझती है कि बिहार का सामाजिक और राजनीतिक ताना-बाना बेहद संवेदनशील है। यहां सत्ता चलाने से ज्यादा मुश्किल उसमें निरंतरता बनाए रखना होता है। ऐसे में अगर पार्टी किसी नए चेहरे या ढांचे के साथ प्रयोग करती, तो पुराने गठबंधन समीकरणों में हलचल हो सकती थी। मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार को यथावत बनाए रखने और दोनों पुराने डिप्टी सीएम को फिर से दोहराने का निर्णय उसी स्थिरता की

गारंटी देता है, जो जनता दल (यू) और बीजेपी के रिश्तों को सहज बनाती रही है। दरअसल, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का लक्ष्य सिर्फ बिहार की सरकार चलाना नहीं, बल्कि आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में राज्य से अपना आधार और सीटें और मजबूत करना है। 2019 के चुनाव में पार्टी और उसकी सहयोगी जदयू ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 में जो हल्की गिरावट दिखी, उसने बीजेपी आलाकमान को यह सोचने पर मजबूर किया कि बिहार में संगठन के साथ-साथ सत्ता में भी सहजता का माहौल बनाकर जनता का भरोसा दोबारा अर्जित किया जाए। इसके लिए विनिंग कॉम्बिनेशन यानी विजयी फॉमूर्ले को न छेड़ना ही सबसे व्यावहारिक रास्ता है।

ऐसा इसलिये है क्योंकि अक्सर राज्य स्तरीय राजनीति में बदलाव संगठनात्मक विचलन लाता है। अगर बीजेपी अपने डिप्टी सीएम या सरकार में चेहरों में बदलाव करती, तो इसका संदेश नीचे के स्तर पर यह जा सकता था कि पार्टी फिर से प्रयोगों के दौर में है। बिहार के मतदाता प्रयोगों से ज्यादा परिणाम देखना चाहते हैं। एक स्थिर सरकार को वे पसंद करते हैं, जो काम में निरंतरता दिखाए। आलाकमान यह समझता है कि बिहार में जो संतुलन नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच तैयार हुआ है, उसी के भरोसे 2029 तक राजनीतिक जमीन तैयार की जा सकती है। नीतीश कुमार का चेहरा अभी भी बिहार की राजनीति में संतुलनकारी माना जाता है। हालांकि उनकी लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वे अभी भी सामाजिक समीकरणों को संभालने वाले नेता के तौर पर स्वीकार्य हैं।

बीजेपी को उनकी यही छवि चाहिए, ताकि वह बड़े पैमाने पर वोटों का ध्रुवीकरण किए बिना ही सत्ता और संगठन दोनों को मजबूत रख सके। यह रणनीति 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी को केंद्र में अपना जनाधार मजबूत रखने के लिए बिहार जैसे बड़े राज्य से कम से कम 35 से अधिक सीटों का लक्ष्य चाहिए। पार्टी जानती है कि इसके बिना उत्तर प्रदेश पर ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा। इसलिए बिहार में यदि गठबंधन स्थिर और प्रभावी रहता है, तो लोकसभा में सीटों की गारंटी लगभग तय मानी जाती है।

इसके अलावा, बिहार से जुड़े अन्य समीकरण भी बीजेपी नेतृत्व के ध्यान में हैं। जातीय जनगणना, आरक्षण और समाज के कमजोर वर्गों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर नीतीश कुमार के माध्यम से सॉफ्ट पोलिटिकल हैंडलिंग की जा रही है। अगर बीजेपी इन मुद्दों को सीधे अपने नेतृत्व में संभालती, तो संभव है विपक्ष इसे ध्रुवीकरण के एजेंडे से जोड़ देता। नीतीश कुमार का रहना इसीलिए बीजेपी के लिए एक कुशन का काम करता है। दूसरी ओर, पार्टी का लक्ष्य राज्य संगठन को मजबूत करने का भी है। सरकार में पुरानी टीम के बने रहने से शीर्ष स्तर पर कोई असंतुलन नहीं होगा, जिससे संगठन जिलों, मंडलों और बूथ स्तर पर चुनावी तैयारियों पर पूरी ऊर्जा लगा सकेगा। जब सरकार और संगठन दोनों में टकराव न्यूनतम होता है, तब लोकसभा चुनाव के लिए ग्राउंड मैकेनिज्म अधिक परिणामकारी बनता है।

बीजेपी की यह रणनीति यह भी दशार्ती है कि वह अब बिहार को सिर्फ सहयोगी दल की राजनीति का मैदान नहीं मान रही। आलाकमान की कोशिश है कि धीरे-धीरे अपना वोट आधार स्वतंत्र रूप से इतना मजबूत किया जाए कि भविष्य में नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों पर निर्भरता कम की जा सके। लेकिन फिलहाल, पार्टी के लिए नीतीश के साथ स्थिर रिश्ते बनाए रखना फायदेमंद सौदा है।

कुल मिलाकर, बीजेपी ने यह निर्णय लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका फोकस अल्पकालिक राजनीतिक लाभ पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक मजबूती पर है। वही पुरानी विनिंग टीम बनाए रखना सिर्फ सत्ता की निरंतरता का प्रतीक नहीं, बल्कि 2029 के लक्ष्य की दिशा में बिछाई जा रही राजनीतिक बिसात का हिस्सा है। बिहार में स्थिरता का यह फॉमूर्ला अगर अगले कुछ वर्षों तक कायम रहता है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका सीधा लाभ मिलने की पूरी संभावना है।

हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद चाल से ममता की सत्ता पर मंडराया संकट

अजय कुमार

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो 15 साल से सत्ता की कमान संभाल रही हैं, अब चारों तरफ से घिरी नजर आ रही हैं। एक तरफ हिंदू वोटरों का झुकाव भाजपा की ओर हो चुका है, तो दूसरी तरफ उनकी मुस्लिम तुष्टिकरण की पुरानी राजनीति भी डगमगा रही है। ताजा संकट खड़ा कर दिया है उनकी ही पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने की नींव रखने का ऐलान कर उन्होंने न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया, बल्कि पूरे राज्य की सांप्रदायिक सियासत को नई हवा भी दे दी। यह घटना महज एक विधायक का विद्रोह नहीं, बल्कि ममता की सत्ता की नींव हिला देने वाली चाल लग रही है।

हुमायूं कबीर कौन हैं, यह जानना जरूरी है। मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से 2021 में तृणमूल के टिकट पर विधायक बने कबीर पहले भी विवादों के केंद्र में रहे हैं। ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके वे मूल रूप से कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं। 2011 में ममता के सत्ता में आने पर वे मंत्री बने, लेकिन 2015 में पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने ममता पर आरोप लगाया कि वे अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को 'राजा' बनाने की कोशिश कर रही हैं। नतीजा यह हुआ कि उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 2021 में वनवास खत्म हुआ और तृणमूल ने फिर मौका दिया। लेकिन अब फिर वही पुरानी कहानी। लोकसभा चुनाव के दौरान कबीर ने कहा था कि मुर्शिदाबाद में 70 फीसद मुस्लिम आबादी है, इसलिए हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो देंगे। यह बयान सुर्खियां बटोर गया। अब बाबरी मस्जिद का राग छेड़कर वे ममता को सीधा चुनौती दे रहे हैं।

6 दिसंबर का दिन खास था। बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी पर कबीर ने बेलडांगा में शिलान्यास किया। कार्यक्रम में तीन लाख लोग जुटे, 40 हजार बिरयानी के पैकेट बंटे और सऊदी से आए धर्मगुरुओं ने आशीर्वाद दिया। मंच से कबीर ने कहा कि तीन साल में मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने 25 नवंबर को ही ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को नींव रखेंगे। तृणमूल ने इसे सांप्रदायिक राजनीति बताकर उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। ममता ने कबीर को आरएसएस का मुखौटा करार दिया। पार्टी का कहना है कि निलंबन बाबरी मुद्दे के लिए नहीं, बल्कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए हुआ। लेकिन कबीर पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि ममता मेरी हत्या भी करवा सकती हैं, लेकिन मस्जिद बनेगी। वे नई पार्टी बनाने और 90 मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं।

यह सब ममता के लिए कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30 फीसद है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 27 फीसद थी, अब बढ़कर 30 के आसपास पहुंच गई। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भरमार है। कबीर का दावा है कि 90 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 35 फीसद से ज्यादा हैं। ममता ने हमेशा अल्पसंख्यक वोटों को सहारा बनाया। इमामों को तनख्वाह, धार्मिक जुलूसों का समर्थन सब कुछ किया। लेकिन अब कबीर की चाल से वोट बंटवारे का खतरा मंडरा रहा। भाजपा को इसका फायदा होगा, जो हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। वीएचपी ने चेतावनी दी कि अगर बाबरी बहाने से हिंदुओं पर हमला हुआ तो कबीर व ममता जिम्मेदार होंगे। हाईकोर्ट ने भी दखल देने से इंकार कर दिया, जिससे कबीर को हौसला मिला।

ममता का मुस्लिम तुष्टिकरण अब उल्टा पड़ रहा है। वक्फ संशोधन कानून पर उनका यू-टर्न इसका बड़ा उदाहरण है। अप्रैल 2025 में ममता ने कहा था कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने दूंगी। तृणमूल ने सड़क से संसद तक हंगामा किया। मुस्लिम समुदाय खुश था। उन्होंने पोर्टल पर वक्फ संपत्ति का ब्योरा अपलोड करने की इजाजत दे दी। इससे मुस्लिमों में गुस्सा भड़का। उन्हें लगने लगा कि ममता भी भाजपा जैसी हो गई हैं। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की तरह वादा किया, लेकिन महागठबंधन की हार देखकर रुख बदला। मुर्शिदाबाद में वक्फ विरोधी हिंसा हुई, जिसमें भाजपा ने ममता पर बांग्लादेश बनाने का आरोप लगाया। मौलाना साजिद रशीदी जैसे नेताओं ने राष्ट्रपति शासन की मांग की। दूसरा बड़ा संकट है विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चुनाव आयोग ने मतदाता सूची साफ करने के लिए एसआईआर शुरू किया। ममता ने इसे अमित शाह की साजिश बताया। कहा कि अगर रोकतीं तो केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा देता। एसआईआर से 46 लाख नाम कट सकते हैं, जिनमें ज्यादातर घुसपैठिए। ममता ने विरोध में रैलियां की। मालदा में कहा कि भाजपा अपनी कब्र खोद रही है। एसआईआर से 40 मौतें हुईं, जिनमें आधे हिंदू। ममता ने मुआवजा देने की घोषणा की और निगरानी टीम बनाई। लेकिन आयोग ने उनकी बाधा को नकार दिया। सीमावर्ती जिलों में वोटरों की संख्या दोगुनी हो गई, जो भाजपा घुसपैठ का सबूत बता रही। बंगाल में एक करोड़ फर्जी वोटर होने का दावा कर रही। मुस्लिम बहुल इलाकों में एसआईआर फॉर्म भरने की होड़ लगी, लेकिन ममता का विरोध जारी है। वे घुसपैठियों को सांत्वना दे रही हैं कि डरें नहीं, वापस बुलाएंगी। 20 साल पहले लोकसभा में घुसपैठ पर बवाल काटने वाली ममता अब उलट बोल रही हैं।

भाजपा इन सबका फायदा उठाने को बेताब है। 2021 में 77 विधायक जीतकर राज्य में मजबूत हुई। अब हिंदू वोट उसके पाले में हैं। वंदे मातरम विवाद से बंगाली अस्मिता जोड़ रही। मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया, ताकि बंगाली मुसलमानों को साधे। ओबीसी लिस्ट से 35 मुस्लिम जातियों को हटाने पर तृणमूल-भाजपा भिड़ गई। जाति सर्वे को भेदभाव बढ़ाने वाला बता रही। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी बंगाल में दखल दे रही, जिस पर भाजपा की मदद का आरोप है। कबीर का बीजेपी से पुराना रिश्ता रहा। 2019 में वे भाजपा से लड़े। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार और भाजपा एजेंट कहा। 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ममता की स्थिति सांप-छछूंदर जैसी हो गई। न निगलते बन रहा, न उगलते। हुमायूं कबीर का खेल कामयाब हुआ तो तृणमूल का वोट बैंक बंट जाएगा। मुस्लिम वोट भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे।

इंडिगो संकट
आसमान पर बढ़ता एकाधिकार

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

भारत के विमानन क्षेत्र में हाल ही में पैदा हुए संकट, जिसकी जड़ें मुख्यतः इंडिगो से जुड़े मामलों में दिखाई देती हैं, ने एक बार फिर यह सच उजागर कर दिया है कि किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक बाजार एकाधिकार कितना बड़ा जोखिम बन सकता है। पिछले एक दशक में इंडिगो ने भारतीय आसमानों में अपना दबदबा इस कदर स्थापित कर लिया है कि उसकी बाजार हिस्सेदारी ने उसे न केवल सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है, बल्कि उसे ऐसे प्रभावशाली स्थान पर बैठा दिया है जहाँ उसकी आंतरिक कमजोरियाँ भी पूरे विमानन क्षेत्र को प्रभावित करने लगती हैं। इंडिगो की तेजी से बढ़ती नेटवर्क क्षमता, प्रतिस्पर्धी किराए और परिचालन कुशलताओं ने इसे शीर्ष तक पहुँचाया, परंतु हालिया व्यवधान यह दर्शाते हैं कि किसी एक कंपनी का बेइंतहा शक्तिशाली हो जाना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर सकता है। इससे जवाबदेही, नियामकीय सतर्कता और प्रतिस्पर्धा की सेहत से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

इस पूरे विवाद के केंद्र में डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) द्वारा जारी किए गए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियम हैं। इन नियमों का उद्देश्य पायलटों और केबिन क्रू को पर्याप्त विश्राम देना है, ताकि थकान से जुड़े जोखिमों को रोका जा सके। दुनिया भर में विमानन नियामक इस विषय पर सख़्त होते जा रहे हैं क्योंकि लगातार उड़ानें भरने के कारण क्रू पर काम का दबाव बढ़ रहा है और प्रशिक्षित पायलटों की कमी एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। भारत में भी सभी एयरलाइनों को पहले से पर्याप्त समय दिया गया था ताकि वे नए नियमों के अनुरूप अपनी स्टाफिंग और शेड्यूलिंग ठीक कर सकें। इसके बावजूद यह सामने आया कि इंडिगो समेत कई एयरलाइंस आवश्यक तैयारियां करने में पिछड़ गईं। इसी कारण उड़ानों में देरी, रद्दीकरण और अव्यवस्था की स्थितियाँ तेजी से बढ़ने लगीं, जिसका खामियाजा लाखों यात्रियों को भुगतना पड़ा।

समस्या की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एक समिति बनाई, ताकि सभी हितधारकों से बातचीत कर समाधान खोजा जा सके। लेकिन असली प्रश्न इंडिगो की तैयारी को लेकर ही उठे। देश का सबसे बड़ा बेड़ा, सबसे अधिक उड़ानें और सबसे व्यापक नेटवर्क रखने वाली इस एयरलाइन का किसी भी महत्वपूर्ण नियम पर देर से प्रतिक्रिया देना सीधे तौर पर पूरे उद्योग को प्रभावित करता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इंडिगो ने जानबूझकर नियमों के अनुरूप तैयारी धीमी की, ताकि वह नियामकों पर दबाव बना सके या कुछ रियायतें हासिल कर सके। यह अनुमान कितना सही है, यह भले ही स्पष्ट न हो, पर यह तथ्य निर्विवाद है कि उसकी तैयारी में कमी ने संकट को कई गुना बढ़ा दिया।

इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी इस समस्या को और जटिल बना देती है। भारतीय घरेलू विमानन बाजार का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा अकेले इंडिगो के पास है। 417 से अधिक विमानों के उसके विशाल बेड़े से प्रतिदिन करीब 2200 उड़ानें संचालित होती हैं। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इंडिगो भारत की घरेलू हवाई यात्रा की रीढ़ बन चुकी है। लेकिन यही स्थिति सबसे बड़ा जोखिम भी है। जब किसी एक कंपनी का प्रभाव इतना व्यापक हो जाए, तो उसकी किसी भी स्तर की कमी या कुप्रबंधन का असर केवल उसके यात्रियों पर नहीं, बल्कि पूरे देश के विमानन संचालन, एयरपोर्ट प्रबंधन और सप्लाई चेन पर पड़ने लगता है। यह निर्भरता बाजार की मजबूती को कम करती है और उसे किसी भी संकट के समय बेहद संवेदनशील बना देती है।इस संदर्भ में संभावित एकाधिकारवादी व्यवहार को लेकर उठे प्रश्न स्वाभाविक हैं। विमानन क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं होता उच्च पूंजी, सख़्त नियम, सीमित स्लॉट और उच्च परिचालन लागत जैसे कारक नई कंपनियों के लिए बड़ी बाधाएँ हैं। ऐसे में किसी एक खिलाड़ी का अत्यधिक बड़ा होना प्रतिस्पर्धा को दबा सकता है और ग्राहकों की

पसंद को सीमित कर सकता है। यदि कोई कंपनी अपने प्रभाव का उपयोग नियमों को प्रभावित करने या संचालन में अनुचित लाभ उठाने के लिए करने लगे, तो यह देश की दीर्घकालिक नीतियों और उपभोक्ता हितों के लिए हानिकारक हो सकता है। मौजूदा संकट इसी बात की याद दिलाता है कि क्या भारत को किसी भी निजी एयरलाइन को इतना बड़ा बनने देना चाहिए कि उसकी चूकें राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता पैदा कर दें?

यात्रियों को तुरंत राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने अस्थायी रूप से नए एफडीटीएल नियमों में कुछ ढील भी दी है। यह कदम यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए उपयुक्त था, क्योंकि अचानक सैकड़ों उड़ानें रद्द होने का खतरा बढ़ गया था। लेकिन ऐसे अस्थायी उपाय स्थायी न बन जाएँ, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। पायलटों के विश्राम से जुड़े नियम सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, न कि किसी एयरलाइन की तैयारी की कमी को ढकने के लिए। भारत को अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों के अनुरूप रहना है और इसके लिए आवश्यक है कि पायलटों को उचित आराम, वैज्ञानिक कार्य-घंटे और सुरक्षित कामकाज का माहौल मिले। यह न केवल सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि भारत की अंतरराष्ट्रीय विमानन छवि को बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य है।

सरकार ने इंडिगो से जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है, जो कि पूर्णतः उचित है। लेकिन इस घटना का दायरा केवल इतनी भर बात तक सीमित नहीं है कि कंपनी ने नियमों का पालन देर से क्यों किया। असल मुद्दा यह है कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का इतना बड़ा हिस्सा जब किसी निजी इकाई पर निर्भर हो, तो उसकी रणनीतियों और तैयारियों का पारदर्शी मूल्यांकन होना चाहिए। यदि कंपनी को पहले से पता था कि नए नियम लागू होंगे, तो अतिरिक्त पायलटों और क्रू की भर्ती समय से क्यों नहीं की गई? क्या नियामकों को स्थिति की असली तस्वीर समय रहते बताई गई? यदि नहीं, तो यह लापरवाही है या गहन प्रबंधकीय कमी? इस पूरे मामले ने डीजीसीए की निगरानी प्रणाली को भी आईना दिखाया है। एक आधुनिक और जटिल विमानन उद्योग में केवल कागजी निगरानी पर्याप्त नहीं होती। आवश्यकता है कि नियामकों के पास तकनीक आधारित रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, डाटा विश्लेषण और चेतावनी तंत्र मौजूद हों,

ताकि किसी भी संभावित संकट को बहुत पहले पहचाना जा सके। यदि नियामक संस्थाएं भविष्यवाणी-आधारित निगरानी विकसित नहीं करेंगी, तो ऐसे संकट बार-बार सामने आएँगे। मौजूदा संकट यह भी स्पष्ट करता है कि किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक एकाधिकार खतरनाक हो सकता है। यह प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है, नवाचार को बाधित करता है और उपभोक्ताओं को सीमित विकल्पों में जकड़ देता है। लेकिन इससे भी बड़ा जोखिम यह है कि पूरा सिस्टम एक ही बिंदु पर निर्भर हो जाता है। स्वस्थ बाजार वही होता है जहाँ कई खिलाड़ी मौजूद हों, जिनसे सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है, विकल्प मिलते हैं और जोखिम विभाजित रहते हैं। भारत के विमानन क्षेत्र के दीर्घकालिक हित इसी में हैं कि बाजार संतुलित रहे और किसी भी एयरलाइन के पास इतना अधिक शक्ति-संतुलन न हो कि वह पूरे उद्योग को प्रभावित करने लगे।यात्री जो इस पूरे उद्योग के केंद्र में हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है विश्वसनीयता, सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता। लगातार रद्द होने वाली उड़ानें, समय पर उड़ान न भरना, और किन्हीं आंतरिक समस्याओं के कारण हुए अव्यवस्था के हालात भारत की उभरती अर्थव्यवस्था की छवि को नुकसान पहुँचाते हैं। भारत तेजी से बढ़ता हुआ देश है और हवाई यात्रा यहाँ आने वाले वर्षों में और अधिक आवश्यक होगी। इसलिए जरूरत है एक ऐसे विमानन पारिस्थितिकी तंत्र की जिसे संकट झेलने की सामर्थ्य हो, जो पारदर्शी, सुरक्षित और यात्री-केंद्रित हो।

आने वाले समय में, नीति-निमार्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे कि कोई भी एयरलाइन अत्यधिक बाजार नियंत्रण न हासिल कर सके। नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, छोटे कैरियर्स को समर्थन, और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने वाले कानून इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उद्देश्य यह नहीं है कि सफल कंपनियों को रोका जाए, बल्कि यह कि उनकी सफलता उद्योग और उपभोक्ता हितों को नुकसान न पहुंचाए। दूसरी ओर, एयरलाइनों को भी यह समझना होगा कि वे केवल एक व्यावसायिक संस्था भर नहीं हैं।

गोवा अग्निकांड

भ्रष्टाचार और लापरवाही की संयुक्त त्रासदी

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

वैश्विक स्तरपर भारत तेजी से शहरी विकास,बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनसंख्या की बढ़ती आर्थिक भागीदारी के दौर से गुजर रहा है,जिसके परिणाम स्वरूप देश के लगभग 780 जिलों में विशाल संख्या में मॉल,मल्टी-स्टोरी बिल्डिंगें, होटल, रेस्टोरेंट,नाइट क्लब, सिनेमाहॉल,सुपर बाजार,कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज और मनोरंजन केंद्रों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इन स्थानों पर प्रतिदिन हजारों-लाखों नागरिक आते हैं, जो आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन इसी विकास की यात्रा के भीतर एक गंभीर प्रश्न भी मौजूद है, भ्रष्टाचार, गैर-जवाबदेही, फायर-सेफ्टी की अनदेखी और प्रशासनिक निरीक्षण की कमी, जो कई बार बड़े हादसों का कारण बन जाती है।

हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में लगी भयंकर आग, जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हुई, इस समस्या का चरम उदाहरण है।इस हादसे ने यह उजागर कर दिया कि देश के अनेक जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान सक्रिय हैं, जिनके पास न तो वैध फायर-सेफ्टी प्रमाणपत्र हैं,न बिल्डिंग बायलॉज की स्वीकृति, न ही नगर परिषद/महानगर पालिका /राज्य सरकार द्वारा जारी आवश्यक लाइसेंस। यह स्थिति केवल प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम नहीं है,बल्कि भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों, लाइसेंसों की अवैध खरीद- फरोख्त,और निरीक्षण एजेंसियों की मिलीभगत का दुष्परिणाम है। जिस प्रकार गोवा के नाइट क्लब को बिना उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलने दिया गया,उसी प्रकार देश के विविध हिस्सों में भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन आम हो चुका है, जिसे रोकने के लिए अब कलेक्टर-स्तर पर स्वतः संज्ञान आधारित निरीक्षण व्यवस्था लागू करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है।

साथियों बात अगर हम भीड़भाड़ वाले प्रतिष्ठानों में सुरक्षा संकट और भ्रष्टाचार की संरचनात्मक भूमिका को समझने की करें तो, भारत में एक ओर जहांआधुनिक मॉल, कैफे, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन केंद्र शहरों की पहचान बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा स्थिति भयावह रूप से कमजोर पाई जाती है।कई जिलों में यह पाया गया है कि(1) फायर-सेफ्टी ऑडिट वर्षों तक नहीं हुए,(2) आपातकालीन निकास अवरुद्ध हैं,(3)फायर-अलार्म और स्प्रिंकलर कार्यरत नहीं (4) बिल्डिंग बायलॉज का पालन न्यूनतम, (5) ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग,(6) अवैध निर्माण और अवैध विस्तार,(7) बिना अनुमति नाइट क्लब, बार, बेसमेंट रेस्टोरेंट और कोचिंग केंद्र संचालन,(8)और सबसे चिंताजनक- भ्रष्टाचार के चलते फर्जी लाइसेंस जारी करना। भारतीय नगर प्रशासन या स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार नई बात नहीं है, लेकिन जब यह भ्रष्टाचार नागरिक जीवन के मूलभूत अधिकार, सुरक्षित वातावरण को खतरे में डाल दे, तब यह केवल रिश्वत का मसला नहीं रहता,बल्कि नागरिकों की हत्या नरसंहार जैसी परिस्थितियों को जन्म देने वाली संरचनात्मक विफलता बन जाता है।गोवा की घटना हो या दिल्ली के मुंडका फायर हादसा, मुंबई का कमला मिल फायर, सूरत का कोचिंग सेंटर मामला,हर घटना के पीछे एक सामान्य कारण दिखाई देता

है:भ्रष्टाचार के बदले मिले फर्जी प्रमाणपत्र और नियमों के क्रियान्वयन में गहरी प्रशासनिक उदासीनता?भारत में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, फायर सेवा अधिनियम, नगर बायलॉज और राष्ट्रीय भवन संहिता जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन जब इन कानूनों के पालन की जिम्मेदारी संभालने वाला निचला - मध्यम प्रशासन ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए, तो सुरक्षा व्यवस्थाएँ केवल कागजी बनकर रह जाती हैं। इसलिए यह मॉडल अब अप्रभावी माना जा रहा है और आवश्यक है कि निरीक्षण का अधिकार सीधे जिलाधिकारी /कलेक्टर के हाथों में आए, जो जिले का सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी होता है और भ्रष्टाचार- रोधी शक्तियाँ भी रखता है।

साथियों बात अगर हम कलेक्टर द्वारा स्वतः संज्ञान आधारित आकस्मिक निरीक्षण की अपरिहार्यता को समझने की करें तो,प्रत्येक जिले में कलेक्टर स्वयं आकस्मिक निरीक्षण करें,वह वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक अत्यंत व्यवहार्य, प्रभावी और नागरिक-हितकारी समाधान है।इसका कारण स्पष्ट है (1) कलेक्टर भ्रष्टाचार-रोधी शक्तियों से लैस होता है।(2) स्थानीय निकाय, नगर परिषद या निगम पर होने वाले राजनीतिक दबाव का प्रभाव कलेक्टर पर कम पड़ता है।

(3) स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति के कारण कलेक्टर किसी भी संस्था पर तात्कालिक जांच और कार्रवाई कर सकता है। (4) आकस्मिक निरीक्षण भ्रष्टाचार की रीढ़ तोड़ने वाला सबसे प्रभावी उपाय है।(5) कलेक्टर की प्रत्यक्ष निगरानी से स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही स्वतः बढ़ जाती है देश में अक्सर देखा गया है कि फायर सेवा विभाग, नगर निगम या लाइसेंसिंग अधिकारी भ्रष्टाचार के कारण बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नियमों के उल्लंघन के बावजूद ह्यक्लीन चिट' दे देते हैं।

ऐसे में यदि कलेक्टर हर जिले में-मॉल, होटल,नाइट क्लब,बड़े रेस्टोरेंट मल्टीप्लेक्स सुपर बाजार,स्कूल/ कॉलेज,कोचिंग सेंटर,और उच्च भीड़- घनत्व वाली इमारतों का स्वतः संज्ञान लेकर निरीक्षण करें, तो नागरिक सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ सकता है कलेक्टर- स्तरीय निरीक्षण से यह भी सुनिश्चित होगा कि फर्जी सर्टिफिकेट रखने वाले प्रतिष्ठानों की तुरंत पहचान की जाए और उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो। गोवा हादसा

इसी बात का प्रमाण है कि यदि जिला प्रशासन सक्रिय रूप से ऐसे प्रतिष्ठानों पर समय- समय पर निगरानी करता, तो शायद 25 निर्दोष नागरिकों की जान बच सकती थी।

साथियों बात अगर हम भीड़- उपस्थितियों वाले संस्थानों पर अनिवार्य नियमित निरीक्षणः एक नई राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता इसको समझने की करें तो, प्रत्येक जिले में सभी ऐसे संस्थानों पर जहाँ बड़ी संख्या में आम जनता एकत्रित होती है, नियमित निरीक्षण व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। यह निरीक्षण त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक न होकर व्यवसाय के प्रकार, भीड़ की मात्रा, जोखिम स्तर और भवन संरचना के आधार पर होना चाहिए।

उदाहरण के लिए,नाइट क्लब, बार, बेसमेंट रेस्टोरेंट मासिक निरीक्षण, मल्टीप्लेक्स, मॉल, भीड़भाड़ बाजार हर तीन माह में निरीक्षण, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सत्रारंभ से पहले अनिवार्य निरीक्षण होटल और गेस्टहाउस प्रत्येक छह माह में निरीक्षण इन निरीक्षणों में निम्न बिंदुओं की सुनिश्चितता आवश्यक है (1) फायर सेफ्टी उपकरणों की कार्यशीलता (2) आपातकालीन निकास मार्ग (3)भीड़ नियंत्रक तकनीक (4) इलेक्ट्रिकल वायरिंग की सुरक्षा(5) एलपीजी/गैस सुरक्षा(6) बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन (7) सुरक्षा कर्मियों की प्रशिक्षित टीम(8) सीसीटीवी और नियंत्रण प्रणाली,भारत में कई हादसों की मुख्य वजह यह रही है कि ऐसे निरीक्षण या तो कभी हुए ही नहीं, या निरीक्षण रिपोर्ट भ्रष्टाचार के कारण कागज में पास दिखाई गई। इसलिए, कलेक्टर-स्तरीय निगरानी के साथ-साथ डिजिटल पब्लिक इन्स्पेक्शन रजिस्टर की व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए ताकि जनता खुद जान सके कि उनके जिले के प्रतिष्ठानों ने कौन-कौन से सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं।

साथियों बात अगर हम सुरक्षा नियमों के पालन की सार्वजनिक घोषणा इंडिया सेफ्टी चार्ट का अनिवार्य प्रदर्शन इसको समझने की करें तो,विश्व के कई देशों में, जैसे सिंगापुर, जापान, कनाडा और जर्मनी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एक पब्लिक सेफ्टी चार्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है। भारत में भी ऐसा मॉडल अपनाने का समय आ चुका है।इस भारत सुरक्षा चार्ट / इंडिया सेफ्टी कम्पलायंस चार्ट में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए- (1)अंतिम फायर सेफ्टी प्रमाणन की तिथि (2) बिल्डिंग बायलॉज अनुपालन स्तर (3) इमरजेंसी निकास योजना(4) अग्निशमन उपकरणों की क्षमता व स्थिति (5) अधिनियमों के अंतर्गत उठाए गए सुरक्षा कदम (6)स्वच्छता और विद्युत सुरक्षा जांच की तिथि (7) कलेक्टर अथवा अधिकृत अधिकारी का डिजिटल सत्यापन, इस चार्ट को रेस्टोरेंट, मॉल, होटल, थिएटर, संस्थानों व नाइट क्लब के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए, ताकि नागरिक स्वयं जान सकें कि जिस स्थान पर वे जा रहे हैं, वह सुरक्षित है या नहीं। यदि कोई प्रतिष्ठान इस चार्ट को प्रदर्शित नहीं करता, तो उसे स्वतः

जोखिम-श्रेणी में रखा जाए और कलेक्टर कार्रवाई करें। साथियों बात अगर हम लाइसेंस उल्लंघन, अवैध संचालन और गैर-अनुपालन पर कठोर कार्रवाई इसको समझने की करें तो,बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर तत्काल लाइसेंस रद्द किया जाए,एक व्यावहारिक और नागरिक- अधिकार आधारित मांग है। भारत में कई बार देखा गया है कि अवैध ढंग से संचालित प्रतिष्ठान- (1)राजनीतिक संरक्षण, (2)पुलिस/नगर निकाय भ्रष्टाचार,(3)या सिस्टम की ढिलाई, के कारण वर्षों तक चलाते रहते हैं। जबकि वे हजारों लोगों की जान खतरे में डालते हैं।

यदि कलेक्टर स्तर पर निम्न नीतियाँ लागू की जाएं-(1)पहली बार में ₹10 लाख तक का जुमार्ना+15 दिन का निलंबन (2) दूसरी बार में लाइसेंस का स्थायी रद्दीकरण(3)तीसरी बार में आपराधिक मुकदमा (आईपीसी 304, 336,337 338 के तहत) तो ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा। नियमों का उल्लंघन केवल प्रशासनिक गलती नहीं है,यह सीधे-सीधे नागरिक जीवन को खतरे में डालने की साजिश है, जो गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। कलेक्टर यदि इसपर कड़ाई से कार्रवाई करें, तो भ्रष्टाचार की श्रृंखला स्वतः टूट जाएगी।

साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार इन सभी हादसों की जड़ का कारण है इसको समझने की करें तो, जनता जानती है,ऐसी लापरवाही बिना नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार की मिलीभगत के संभव ही नहीं। यह एक संरचनात्मक समस्या है, जिसमें शामिल होते हैं-निरीक्षण अधिकारी,लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी,स्थानीय निकाय कर्मचारी, राजनीतिक दबाव,भ्रष्ट ठेकेदार और बिल्डर और कभी-कभी पुलिस जब भ्रष्टाचार नियमों का स्थान ले लेता है तो,(1)आग सुरक्षा कागजों में पास हो जाती है,(2)लाइसेंस रिश्वत के आधार पर जारी हो जाता है,(3) निरीक्षण रिपोर्ट फर्जी तैयार हो जाती है,(4)अवैध निर्माण को अनदेखा कर दिया जाता है,(5) और किसी दुर्घटना से पहले कोई कार्रवाई नहीं होती।

गोवा का नाइट क्लब हादसा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां,(1) अवैध विद्युत कनेक्शन,(2) फर्जी लाइसेंस,(3)ओवर-कैपेसिटी भीड़ (4) आपातकालीन निकास बंद,और (5)फायर सिस्टम गैर-कार्यशील,जैसी खामियाँ बाद में सामने आईं। यह सब केवल एक ही चीज की ओर इशारा करता है-भ्रष्टाचार व प्रशासनिक उदासीनता। इसलिए भारत को अब एक ऐसी प्रणाली अपनानी चाहिए जिसमें-भ्रष्टाचार का जोखिम न्यूनतम, निरीक्षण डिजिटल, लाइसेंसिंग पारदर्शी, और जिम्मेदारी शीर्ष स्तर पर निश्चितहो।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत वर्तमान में एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आर्थिक विकास की तेज रफ्तार, शहरीकरण का विस्तार, व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बढ़ती संख्या के बीच नागरिक सुरक्षा की चुनौती दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है।

गोवा नाइट क्लब की आग में 25 लोगों की दर्दनाक मृत्यु इस बात की चेतावनी है कि यदि हम भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही व निरीक्षण तंत्र की विफलताओं को तुरंत ठीक नहीं करते,तो ऐसे हादसे भविष्य में भी सामने आते रहेंगे आवश्यक है कि कलेक्टर-स्तरीय स्वतः संज्ञान अनिवार्य नियमित निरीक्षण, सार्वजनिक सुरक्षा चार्ट का प्रदर्शन, उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई, भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्र का सशक्तिकरण उपायों को लागू किया जाए।

Balaji Traders

Our Other Brands

Ro Water Purifier

Apne ghar ko dijiye shuddh aur surakshit paani ka tohfa
RO purifier ke saath sehat ka vada

पानी ऐसा, जिस पर आप आँख मूंदकर भरोसा करें

Marketing & Manufacturers by Balaji Traders

- 100% Pure & Safe Water
- Advanced 7 Stage Purification
- Retains Essential Minerals
- Removes Bacteria & Viruses

Place your order : www.balajiwaterpurifier.com

कर्नाटक की सियासत में अब डीके रहेंगे या सिद्धारमैया

स्वदेश कुमार

कर्नाटक की राजनीति में इस समय एक बड़ा राजनीतिक घमासान चल रहा है, जिसका केन्द्र बिंदु उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर टकराव है। दोनों के बीच विवाद इतना गहरा हो गया है कि जिससे पार्टी के अंदर मतभेद साफ नजर आने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए यह परिस्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है क्योंकि दोनों नेताओं की महत्त्वाकांक्षाएं और राजनीतिक दबाव पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर संकट उत्पन्न कर रहे हैं। डीके शिवकुमार राजनीतिक रूप से कर्नाटक में अपनी पकड़ मजबूत करते आ रहे हैं। वे लंबे समय से पार्टी के मुख्य नेतृत्व में सक्रिय रहे हैं और उनकी पकड़ पार्टी के अधिकांश कार्यकताओं व नेताओं के बीच है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के मामले में कोई समझौता करने का मन नहीं बनाया। शिवकुमार का मानना है कि उनके अनुभव, जनाधार, और राजनीतिक योगदान के कारण वे इस पद के लिए अधिक योग्य हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह भी संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से कम पर वे कभी सहमत नहीं होंगे।

सिद्धरमैया, जो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे भी अपनी कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उनकी भी पार्टी में अपनी पकड़ है और वे भी इस पद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिद्धरमैया के समर्थक भी उनकी सरकार को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और किसी भी तरह की बगावत को पार्टी हित के खिलाफ मानते हैं। इसलिए उनके लिए यह कुर्सी छोड़ना कोई आसान फैसला नहीं है।इस बीच, पार्टी के आलाकमान के लिए स्थिति काफी पेचीदा हो गई है। दोनों नेताओं के बीच हो रहे इस टकराव ने कांग्रेस के रणनीतिक कमजोरियों को उजागर कर दिया है। बगावत इतनी बढ़ चुकी है कि अगर पार्टी नेतृत्व समय

पर सही और संतुलित निर्णय नहीं लेता है तो इसका असर विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। खासकर जब पार्टी को कर्नाटक में अपनी पकड़ और संगठन को मजबूत करने की जरूरत है।

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की राय में अगर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस विवाद को शांति से नहीं सुलझाते हैं, तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह टकराव आज केवल मुख्यमंत्री पद का नहीं रहा, बल्कि दोनों के समर्थक भी अलग-अलग मोर्चे पर खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शिवकुमार के समर्थक तो यहां तक कि बीजेपी से भी संपर्क करने में गुरेज नहीं कर रहे, जो कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक स्थिति है। यह संकेत है कि अगर पार्टी आलाकमान ने समय रहते स्पष्ट निर्देश या मध्यस्थता नहीं की, तो शिवकुमार के नेतृत्व में पार्टी के भीतर अलगाव या विघटन की संभावना भी जताई जा रही है।पार्टी नेतृत्व ने फिलहाल इस मामले में चुप्पी साध रखी है, लेकिन खबरों के अनुसार राहुल गांधी ने पक्षों की बात सुननी शुरू कर दी है। इसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। परंतु इधर दोनों पक्षों के खेमे भी अपनी-अपनी दलीलों को पार्टी अध्यक्ष तक पहुँचा चुके हैं। दोनों ओर से इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी फैसला आएगा, वह उनके लिए स्वीकार्य होगा। लेकिन राजनीतिक धरातल पर देखा जाए तो ऐसा होना मुश्किल लगता है क्योंकि दोनों नेताओं की महत्वाकांक्षाएं इतनी मजबूत हैं कि वे दोनों ही कम समझौता करने को तैयार नहीं हैं।इस विवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर सशक्त नेतृत्व की कमी उजागर हो रही है। ऐसी स्थिति में पार्टी के लिए जरूरी होगा कि वह जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकाले ताकि आगे बढ़कर चुनाव तैयारी और संगठन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यदि लंबे समय तक यह विवाद बना रहा तो इससे पार्टी के कार्यकर्ता भी निराश हो सकते हैं और विरोधी दलों को भी यह मौका मिलेगा कि वे इसका राजनीतिक लाभ उठाएं। यह मुद्दा कर्नाटक की राजनीति में भी हलचल मचा रहा है। विपक्षी दल इसे कांग्रेस में अंदरुनी फूट के रूप में दिखा रहे हैं और अपनी ताकत बताने का मौका तलाश रहे हैं। यदि कांग्रेस ने इस विवाद को संभाला नहीं तो कर्नाटक में उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। ऐसे हालात में पार्टी नेतृत्व के सामने चुनौती यह है कि वे दोनों प्रमुख नेताओं के बीच सामंजस्य बनाएं और पार्टी की एकजुटता को बनाये रखें। राजनीतिक जमावट और नेताओं के बीच सत्ता की होड़ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही है कि कांग्रेस के लिए समय रहते सही निर्णय लेना बेहद जरूरी हो गया है।कर्नाटक की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए यह लड़ाई अब केवल पद की नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली भी हो गई है। पार्टी आलाकमान की भूमिका इस मामले में निर्णायक साबित होगी और राहुल गांधी की मंशा पर सभी की नजरें टिकी हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी किस तरह का निर्णय लेंगे और वह कैसे दोनों पक्षों को संतुष्ट करेंगे। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के लिए अब यह मामला केवल नेतृत्व का नहीं, बल्कि समूचे संगठन की स्थिरता का प्रश्न बन चुका है। प्रदेश की राजनीति में जो भी हो, उसका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे जाने की संभावना है, क्योंकि कर्नाटक हमेशा से कांग्रेस की महत्वपूर्ण राजनीतिक जंग का मैदान रहा है। इस समय कांग्रेस नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह गणना से काम लेकर विवाद को जल्द से जल्द समाप्त कराए। तभी पार्टी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी और आगामी चुनावों में बेहतर स्थिति में नजर आएगी।

नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार

ललित गर्ग

नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में है और यह बड़ी उपलब्धि एवं परिवर्तन आकस्मिक नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सुनियोजित, कठोर और व्यापक रणनीतियों का परिणाम है। वर्षों से जिस समस्या ने भारत के हृदयस्थल को रक्तरंजित किया था, जिस विचारधारा ने दशकों तक विकास, सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं को बंधक बनाए रखा था, वह अब लगभग समाप्ति की कगार पर पहुँच चुकी है। इसका सबसे बड़ा और हालिया प्रमाण है देश के सबसे खतरनाक, खूंखार और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा का खात्मा, एक ऐसा नाम जिसके आतंक ने न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि पूरे तंत्र को लंबे समय तक चुनौती दी। सुकमा क्षेत्र में जन्मा हिड़मा, सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य था और पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन-1 का प्रमुख। उसकी मौजूदगी मात्र से बड़े-बड़े हमले अंजाम दिए जाते थे। 2010 का दंतेवाड़ा हो या फिर 2013 का झीरम घाटी हमला, पिछले 20 बरसों में हुए लगभग सभी बड़े नक्सली हमलों के पीछे हिडमा का हाथ माना जाता है। उसने लंबे अरसे तक दंडकारण्य में आतंक का राज कायम रखा। दरभा घाटी नरसंहार तक, सुरक्षा बलों के कई घातक ऑपरेशनों का गुनाहगार हिड़मा रहा। उसकी धमक इतनी थी कि उसके सिर पर 50 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक का इनाम घोषित था। लेकिन 18 नवंबर 2025 को सुरक्षा बलों के एक अत्यंत सटीक और साहसपूर्ण अभियान में हिड़मा और उसकी पत्नी राजे सहित छह माओवादी ढेर हुए।

मौके से मिली एके-47, पिस्टल, राइफलें और अन्य हथियार यह प्रमाणित करते हैं कि यह ऑपरेशन नक्सलवाद की रीढ़ पर निर्णायक प्रहार है। हिड़मा का अंत प्रतीकात्मक ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी एक ऐसा क्षण है जिसने नक्सली नेटवर्क को हिला कर रख दिया है। लंबे समय से 'लाल गलियारा' कहे जाने वाले क्षेत्र की गतिविधियाँ जिस तेजी से सिकुड़ रही हैं, वह दशार्ता है कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर जिस दोहरी रणनीति को अपनाया है, उसने वास्तविक जमीन पर असर दिखाया है। मार्च 2026 तक 'नक्सलमुक्त भारत' अभियान के अंतर्गत इस साल 300 नक्सली मारे गए, सैकड़ों गिरफ्तार हुए और आत्मसमर्पण किया-यह आँकड़े बताते हैं कि नक्सलवाद अब अपनी वैचारिक और संगठनात्मक शक्ति खो चुका है। हाल ही में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दो दिनों में सैकडों नक्सलियों का आत्मसमर्पण होना यह दशार्ता है कि नक्सल संगठन अब अपने आधार क्षेत्रों में भी समर्थन खो रहा है, और आदिवासी समाज धीरे-धीरे सरकारी विकास योजनाओं की ओर बढ़ रहा है। इसी परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है हिड़मा का खात्मा, जिसने माओवादी कमान में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है, जिसकी भरपाई उनके लिए आसान नहीं होगी।

आतंकवाद की तरह ही नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक, गहरी और जटिल चुनौती रहा है। जिस तरह सीमा पार से आने वाला आतंकवाद देश की शांति, विकास और

सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बना हुआ था, उसी तरह भीतर से जन्मा नक्सलवाद राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करता रहा। दशकों तक यह समस्या न सिर्फ कुछ राज्यों के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए चिंता और असुरक्षा का कारण रही। लेकिन अब जिस निर्णायक मोड़ पर देश खड़ा है, वह यह संकेत देता है कि नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। हाल के वर्षों में लगातार मिल रही सफलताएँ, शीर्ष नक्सली कमांडरों का सफाया, व्यापक आत्मसमर्पण, और प्रभावित क्षेत्रों में तेज विकास-ये सभी इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि देश एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। यह वह सुबह है जो भारत को भय, हिंसा और पिछड़ेपन से मुक्त कर, स्थायी शांति और तेज विकास की ओर ले जाती है।

नक्सलवाद की जड़ें स्वतंत्रता के बाद की सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, भूमि अधिकारों और आदिवासी इलाकों की उपेक्षा में थीं। कई क्षेत्रों में विकास की रोशनी नहीं पहुँची थी, सरकारी योजनाएँ कागजों में रह जाती थीं, और स्थानीय समुदाय प्रशासन के प्रति अविश्वास से भरे हुए थे। इस वातावरण में नक्सली संगठनों को जमीन और जनसमर्थन मिला। उन्होंने वर्ग संघर्ष और हथियारबंद क्रांति के नाम पर हिंसा का मार्ग अपनाया, जंगलों को अपनी ढाल बनाया और आदिवासी युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया। धीरे-धीरे यह आंदोलन एक साम्यवादी विचारधारा का रूप लेते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक चुनौती बन गया। लेकिन समय के साथ यह आंदोलन अपनी मूल विचारधारा से हटकर आतंक, वसूली, शोषण और खून-खराबे का अड्डा बन गया। सुरक्षा बलों पर हमले, विकास कार्यों को बाधित करना, पुलों और स्कूलों को उड़ाना, आदिवासियों को ढाल बनाना, और सत्ता हासिल करने की लालसा-यह सब नक्सलवाद की असलियत बन गया। इस मानसिकता ने न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दी, बल्कि हजारों परिवारों को तबाह किया और लाखों लोगों के जीवन को भय से भर दिया। लेकिन मोदी एवं शाह के प्रयासों से न केवल नक्सलवाद के खात्मे की सफल लड़ाई लड़ी गयी बल्कि नक्सल क्षेत्रों में विकास की योजनाओं को लागू किया गया। सड़क-बिजली-मोबाइल नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में काफी काम हुआ है और इससे भी नक्सलियों की पकड़ कमजोर करने में मदद

मिली है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2014 से अभी तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 12 हजार किमी से ज्यादा सड़कें बनी है, बैंकों की हजार से ज्यादा शाखाएं खोली गई है और स्किल डिवेलपमेंट पर काम किया जा रहा है। इन समन्वित प्रयासों से ही नक्सली जड़ से उखड़ेंगे।

माड़वी हिड़मा जैसे अत्यंत खूंखार और रणनीतिक दिमाग वाले नेता का मारा जाना, नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ने जैसा है। हिड़मा न सिर्फ नक्सलियों की सैन्य रणनीतियों का प्रमुख दिमाग था, बल्कि उसकी छवि ने वर्षों तक सुरक्षा बलों में चुनौती की भावना जगाई रखी। नक्सलवाद के कमजोर होने में केवल सुरक्षा अभियानों की भूमिका नहीं है, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति सबसे महत्वपूर्ण रही है। जब सरकार ने स्पष्ट किया कि देश को ह्लनक्सलवाद मुक्त भारतह्व बनाना है, तो उसके लिए बहु-स्तरीय रणनीति अपनाई गई। एक ओर सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और सटीक इंटेलिजेंस से मजबूत किया गया, वहीं दूसरी ओर सड़कें, स्कूल, अस्पताल, दूरसंचार और आजीविका कार्यक्रमों द्वारा विकास को तेज किया गया। विकास और सुरक्षा का यह संयुक्त प्रभाव नक्सलवाद की जड़ों को खोखला करने में निर्णायक सिद्ध हुआ है।

देश के सामने जो नई सुबह उभर रही है, उसका अर्थ सिर्फ यह नहीं कि बंदूकें शांत हो जाएँगी। इसका अर्थ यह भी है कि वे क्षेत्र, जो दशकों से पिछड़े थे, अब देश की मुख्यधारा से जुड़ेंगे। वहाँ निवेश होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत होगा, पर्यटन और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, और लोग भय-मुक्त होकर जीवन जी पाएँगे। नक्सलवाद के पतन का संदेश यह भी है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी हिंसक विचारधारा से अधिक शक्तिशाली है। हथियार, भय और आतंक से सत्ता पाने का कोई भी प्रयास अंततः असफल होता है। जनता की आकांक्षाएँ सदैव विकास, सुरक्षा और शांति में होती हैं। नक्सली आंदोलन की जैसी समाप्ति दिख रही है, वह इस सत्य को और अधिक स्पष्ट करती है। नक्सलवाद की पूर्ण समाप्ति केवल बंदूक से नहीं होगी। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार विकास योजनाओं की निरंतरता बनाए रखे, आदिवासी समुदायों को सशक्त करे, स्थानीय संस्कृति और संसाधनों का सम्मान करे, और यह सुनिश्चित करे कि प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और संवेदनशील बने। यदि यह निरंतरता जारी रहती है, तो नक्सलवाद का पुनरुत्थान असंभव हो जाएगा। नक्सलवाद का लगभग खत्म होना भारत के लिए सिर्फ एक सुरक्षा उपलब्धि नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह उस संघर्ष का अंत है जिसमें हजारों जवानों ने बलिदान दिया, लाखों नागरिकों ने दशकों तक आतंक सहा, और देश ने विकास की गति रोककर भी सुरक्षा को प्राथमिकता दी। आज जब नक्सलवाद ढह रहा है, तब यह केवल सरकार की सफलता नहीं, बल्कि भारत की सामूहिक विजय है। यह एक नए भारत की सुबह है-शांत, सुरक्षित, विकासशील और आत्मविश्वासी। ऐसी सुबह जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को प्रकाश से भर देगी।

जमी बर्फ पिघली, दोस्ती की नई शुरूआत

प्रमोद तिवारी

भारत और कनाडा के रिश्तों पर जमी कड़वाहट की बर्फ अब धीरे-धीरे पिघलने लगी है। दोनों देशों के बीच भरोसे और सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। बदलते वैश्विक हालात और व्यापारिक जरूरतों ने दोनों देशों को एक बार फिर साथ आने के लिए प्रेरित किया है। जून से शुरू हुई यह सकारात्मक पहल अब धरातल पर दिखने लगी है, जिसे हालिया बैठकों और आर्थिक समझौतों में साफ महसूस किया जा सकता है। इस बदलते रिश्ते की सबसे बड़ी झलक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के उस लक्ष्य में दिखती है, जिसमें उन्होंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक ले जाने का संकल्प लिया है। वहीं, कनाडा द्वारा नागरिकता के दरवाजे फिर से खोलने की घोषणा इस बात का प्रमाण है कि कूटनीतिक कड़वाहट अब खत्म हो रही है। यह महज एक व्यापारिक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस नए युग की आहट है जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा। एक दौर वह भी था जब खालिस्तानी गतिविधियों और राजनीतिक आरोपों के चलते दोनों देशों के बीच गहरी खाई पैदा हो गई थी। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान यह खटास सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगी थी, जिससे दशकों पुराने सांस्कृतिक और जन-आधारित संबंधों को नुकसान पहुँचा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कनाडा में नई सरकार और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व ने रिश्तों को नई ऊर्जा और आत्मीयता प्रदान की है। उन्होंने पुरानी गलतियों और अवरोधों को पीछे छोड़कर भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दोनों देशों को अब यह अहसास हो चुका है कि आपसी विवाद में किसी का भला नहीं है। व्यापारिक अवसरों और सामरिक जरूरतों ने संवाद के नए पुल बना दिए हैं, जो आने वाले समय में दोनों देशों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी की जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। यह मुलाकात भले ही मुख्य सत्रों के इतर हुई, लेकिन उसका संदेश अत्यंत गहरा और दूरगामी था। यहां दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी इनोवेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और कनाड़ा के पास डिफेंस, स्पेस, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी और एजुकेशन समस्त कई क्षेत्रों में सहयोग एवं सहमति बढ़ाने के मौके हैं। यह सहमति केवल औपचारिकता नहीं बल्कि रिश्तों को एक नए मोड़ पर लाने का संकेत थी। कनाडा एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी शक्ति है और भारत विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी प्रतिभा का केंद्र बन चुका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं जिनकी दिशा अब खोली जा रही है। वैसे भी भारत के स्टूडेंट्स के लिये अब भी कनाड़ा सबसे पसंदीदा जगहों में एक हैं। कनाडा अपने नागरिकता कानून में भी बदलाव करने जा रहा है, उससे भी भारतीयों को फायदा होने की व्यापक संभावनाएं है।

पीयूष गोयल के वक्तव्य में दिखती आर्थिक साझेदारी की दृष्टि इस बात का परिचायक है कि भारत और कनाडा अब केवल राजनीतिक संवाद से आगे बढ़कर व्यावहारिक सहयोग के नए आधार बना रहे हैं। 50 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य बेहद महत्वाकांक्षी है, लेकिन यह उन आर्थिक संभावनाओं का वास्तविक अनुमान भी है जो दोनों देशों की नीतियों, संसाधनों और क्षमताओं में मौजूद है। भारत कनाडा के लिए एक विशाल बाजार है और कनाडा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा, खनिज, कृषि और तकनीकी साझेदार। इसी परस्पर निर्भरता और जरूरत ने दोनों देशों को फिर से एक-दूसरे की ओर कदम बढ़ाने के लिए

प्रेरित किया है। अब जरूरी है कि विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी रखते हुए जल्द समझौते तक पहुंचा जाये।

हाल के वर्षों में दुनिया बहुध्रूवीय स्वरूप की ओर बढ़ रही है। अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस और पश्चिम एशिया जैसे शक्ति केंद्रों के बीच उभर रही नई अनिश्चितताओं ने मध्यम और उभरती शक्तियों को नए साझेदार तलाशने के लिए विवश किया है। भारत और कनाडा इस वैश्विक संरचना में ऐसे दो देश हैं जिनके पास जनसांख्यिकीय शक्ति, आर्थिक संसाधन, शिक्षा-तकनीक की क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों का साझा आधार मौजूद है। ऐसे में इन दोनों का साथ आना न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए आवश्यक है बल्कि एक नई वैश्विक संरचना के निर्माण में भी उपयोगी हो सकता है। यह संरचना सहयोग, नवाचार, जलवायु न्याय, हरित तकनीकों और स्थायी विकास पर आधारित हो सकती है। कनाडा में भारतीय मूल की बड़ी आबादी दोनों देशों के रिश्तों को मानवीय और सामाजिक आधार भी देती है। जब भी रिश्तों में तनाव आया, प्रवासी भारतीय समुदाय उसके बीच पुल की तरह खड़ा दिखाई दिया है। यही समुदाय आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक रिश्तों को नई दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह समुदाय न केवल कनाडा के आर्थिक विकास का हिस्सा है बल्कि भारत-कनाडा संबंधों की गहरी कड़ी भी है। यही कारण है कि दोनों सरकारों ने इस सामाजिक संबंध को

> **2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक ले जाने का संकल्प लिया है। वहीं, कनाडा द्वारा नागरिकता के दरवाजे फिर से खोलने की घोषणा इस बात का प्रमाण है कि कूटनीतिक कड़वाहट अब खत्म हो रही है।**

और मजबूत करने का प्रयास शुरू किया है जिससे गलतफहमियाँ कम हों, लोगों के बीच भरोसा बढ़े और राजनीतिक विवादों का असर द्विपक्षीय रिश्तों पर सीमित रहे।

वर्तमान दौर में भारत की वैश्विक छवि एक निर्णायक, प्रभावशाली और विश्व-हितैषी शक्ति के रूप में उभर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक शैली, वैश्विक मंचों पर सक्रियता और विकास-शांति आधारित विदेश नीति ने भारत की स्थिति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दूसरी ओर कनाडा भी एक स्थिर लोकतंत्र और बहुसांस्कृतिक देश के रूप में वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। दोनों देशों की यह समान सोच और नई वैश्विक चुनौतियों के प्रति साझा दृष्टिकोण अब आपसी सहयोग के लिए अधिक अनुकूल अवसर पैदा कर रहा है। समीक्षा के इस चरण में यह स्पष्ट है कि भारत-कनाडा संबंधों में आया यह सकारात्मक मोड़ केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि गहरे आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक हितों पर आधारित है। मार्क कार्नी सरकार को भी यह समझ आ रही है कि भारत जैसे मजबूत साझेदार से दूरी कनाडा की आर्थिक और वैश्विक भूमिका के लिए सही नहीं। वहीं भारत भी उन देशों के साथ संबंधों का विस्तार चाहता है जो तकनीक, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और नवाचार के क्षेत्रों में मूल्यवान साझेदारी दे सकते हैं। यही वजह है कि दोनों देश अब नयी समझ विकसित करते हुए एक ऐसे दौर की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें संवाद, सहयोग और परस्पर सम्मान केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में शुरू हुई यह नई गर्माहट एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह बदलाव न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा बल्कि वैश्विक शांति, नई तकनीक, हरित विकास और सामाजिक सौहार्द की दिशा में भी नई संभावनाएँ खोलेगा। दोनों देश यदि इसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते रहे तो यह केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती नहीं देगा, बल्कि एक नई विश्व संरचना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सर्दियों में फायदेमंद गुड़, तिल और मूंगफली

चेतन चौहान

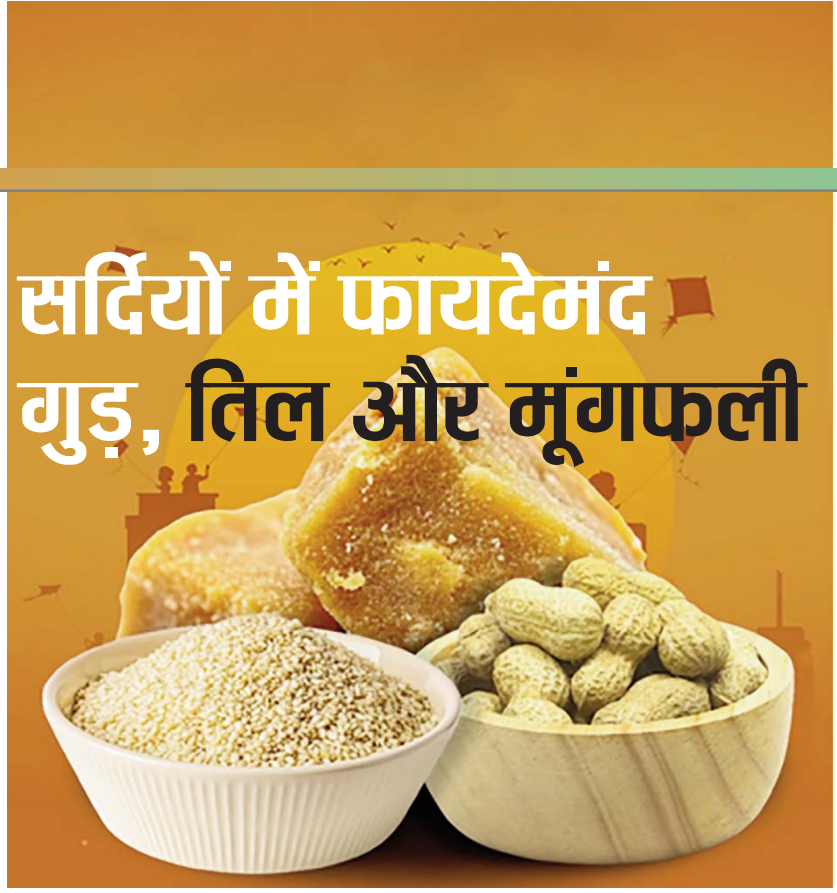

बसंत ऋतु की तरह सर्द ऋतु भी सुहावनी होती है। शीतल पवन, धुंध, हल्की फुहारें एवं स्वच्छ वातावरण की शीतलता जहां मन को लुभाते हैं, वहीं धूप में बैठकर सर्द मौसम की मेवा का आनंद सेहतमंद बनाता है।

सर्दियों में गुड़, तिल और मूंगफली से बनाई गई खास सामग्री हर किसी को अच्छी लगती है। इस मौसम में गुड़, तिल और मूंगफली का नियमित सेवन करने से सर्दी से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। आयुर्वेद में तिल और गुड़ का मिश्रित सेवन असरकारक औषधि के रूप में जाना जाता है। तिल मिश्रित जल से स्नान एवं जल का पान, तिल मिश्रित गुड़ का लड्डू, तिल के तेल द्वारा शरीर में मालिश और तिल से ही यज्ञ में आहुति करने से तन और मन दोनों के विकार नष्ट होते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़ और मूंगफली का सेवन करना बेहद गुणकारी माना गया है, आइए जानते हैं.

▶ कुरकुरे स्वाद और गर्म तासीर वाली मूंगफली, तिल मिश्रित गुड़ न केवल पौष्टिकता का खजाना है, बल्कि प्रोटीन, कैलोरीज, विटामिन बी, ई, तथा के, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, नियासिन, जिंक का अच्छा स्रोत भी होता है।

▶ तिल, गुड़ और मूंगफली गरीबों की मेवा कही जाती है। काले और लाल तिल और गुड़ में लौह तत्वों की भरपूर मात्रा पायी जाती है, जो रक्तअल्पतता के इलाज में कारगर साबित होती है।

▶ काले और सफेद तिल के अलावा लाल तिल भी होता है। सभी के अलग-अलग गुण होते हैं। काला तिल पौष्टिक माना जाता है।

इसमें गर्म, कसैला, मीठा और चरपरा स्वाद भी पाया जाता है।

▶ मूंगफली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व कई बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। जबकि तिल में मीथोनाइन और ट्रायप्टोफन नामक दो बहुत महत्वपूर्ण एमिनो एसिड्स भी होते हैं, जो अन्य शाकाहारी खाद्य पदार्थों में नहीं होते।

▶ ट्रायोप्टोफन को शांति प्रदान करने वाला तत्व भी कहा जाता है, जो गहरी नींद लाने में सक्षम है। यही त्वचा और बालों को भी स्वस्थ रखता है। मीथोनाइन लीवर को दुरुस्त रखता है और कॉलेस्ट्रोल को भी नियंत्रित रखता है।

▶ तिल हजम करने के लिहाज से भारी होता है। तिल मिश्रित गुड़ खाने में स्वादिष्ट, सेहतमंद और कफनाशक होता है। यह बालों के लिए मजबूती और दांतों की समस्या दूर करने के साथ ही यह श्वास संबन्धी रोगों में भी लाभदायक होता है।

▶ तिल स्वभाव से गर्म होता है, इसलिए इसे सर्दियों में गुड़ के साथ खाया जाता है। गजक, रेवड़ियां और तिल के बने लड्डू खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। सर्द ऋतु में गुड़ और काले तिल के लड्डू खाने से जुकाम, खांसी, दमा, ब्रॉन्काइटिस आदि रोग दूर होते हैं।

▶ गुड़ मिश्रित तिल की तिलपट्टी, मूंगफली मावा बाटी, स्पेशल तिल गजक पराठा, रेवड़ी, तिल्ली, मावा, मिक्स तिल्ली, गजक रोल व गजक प्लेन सहित गुड़ व मूंगफली के कई तरह स्पेशल तिल पट्टी स्वादिष्ट के साथ-साथ पौष्टिक भी होता है।

▶ तिल में विटामिन ए व सी छोड़कर वे सभी आवश्यक पौष्टिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तिल विटामिन बी व आवश्यक फैटी एसिड्स से भरपूर है।

▶ प्रतिदिन पचास ग्राम तिल के चूर्ण को गुड़, शक्कर या मिश्री के साथ मिलाकर फांक लेने से कब्ज संबंधी समस्या से निजात मिलती है। तिल बीज स्वास्थ्यवर्धक वसा का बड़ा स्रोत है, जो चयापचय को बढ़ाता है और कब्ज को दूर करता है।

▶ तिल बीजों में उपस्थित पौष्टिक तत्व, जैसे- कैल्शियम और आयरन त्वचा को कांतिमय बनाए रखते हैं। इसमें न्यूनतम सैचुरेटेड फैट भी होते हैं, इसलिए इससे बने खाद्य पदार्थ उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है।

▶ मूंगफली में मेवा, अनाज व मीट आदि में पाया जाने वाला विटामिन बी-3 मिलता है। यह विटामिन अल्ट्रा वॉयलेट किरणों से होने वाले स्किन कैंसर को रोकने में अधिक प्रभावी है।

▶ तिल में उपस्थित लेसिथिन नामक रसायन कोलेस्ट्रोल के बहाव को रक्त नलिकाओं में बनाए रखने में मददगार होता है।

▶ गुड़ के साथ पकाए चावल खाने से बैठा हुआ गला व आवाज खुल जाती है। गुड़ और काले तिल के लड्डू खाने से सर्दी में अस्थमा बीमारी में राहत मिलती है।

▶ तिल और गुड़ के लड्डू उन बच्चों को सुबह और शाम को जरूर खिलाना चाहिए, जो रात में बिस्तर गीला कर देते हैं। तिल के नियमित सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है।

▶ गुड़ और घी मिला कर खाने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। तिल और गुड़ का हलवा खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है।

SAKARNI PLASTER (INDIA) PRIVATE LIMITED
D Mall 405, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034
customercare@sakarni.com | +91-9810177365 | www.sakarni.com

मुक्ति देने वाली शिक्षा की जरूरत

राष्ट्र समाज

हर वर्ष 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन केवल औपचारिक उत्सव का नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र के चरित्र, संस्कृति और सृजनशीलता का आधार है। यह दिवस स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता का सबसे सशक्त माध्यम माना। वे न केवल एक प्रखर राष्ट्रनायक थे बल्कि एक दूरदर्शी विचारक भी थे जिन्होंने कहा था कि 'शिक्षा वह शेरनी है, जिसके दूध को पीने के लिए साहस चाहिए।' मौलाना आजाद का मानना था कि भारत की शिक्षा पद्धति ऐसी हो जो हर वर्ग, हर समुदाय, हर व्यक्ति को अवसर दे। उन्होंने प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक सबके लिए समान अवसर की बात कही। उनका सपना था कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम न रहकर जीवन को दिशा देने वाली प्रक्रिया बने। आज जब हम उनके विचारों की ओर देखते हैं तो यह महसूस होता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ने तकनीकी रूप से प्रगति की है, मानवीय दृष्टि और मूल्य शिक्षा में कमी आई है। हमारी शिक्षा शांतिप्रिय, अहिंसक एवं सर्वांगीण विकसित बनाने की बजाय हिंसक, बीमार एवं अशांत बना रही है।

आज भारत की शिक्षा व्यवस्था में अनेक विसंगतियां हैं। शिक्षा आज ज्ञान की जगह अंक और प्रमाणपत्र की होड़ बन चुकी है। विद्यार्थी रट्टा मारने की मशीन बनते जा रहे हैं, सोचने और सृजन करने की क्षमता कुंठित हो रही है। शिक्षा में नैतिकता, सह-अस्तित्व, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्य गौण हो गए हैं। समाज में शिक्षक की प्रतिष्ठा घटती जा रही है, वे अब प्रेरणा के स्रोत की बजाय 'सिलेबस पूरा करने' वाले कर्मचारी बनते जा रहे हैं। शहरी और ग्रामीण शिक्षा में गहरी असमानता है, शहरों में अत्याधुनिक विद्यालय हैं तो गाँवों में अब भी शिक्षा सुविधाओं का अभाव है। देश में लाखों एकल शिक्षक विद्यालय है। डिग्रियाँ बढ़ रही हैं पर रोजगार घट रहे हैं, शिक्षा और जीवन की आवश्यकताओं में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। इन विसंगतियों को दूर करना ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की वास्तविक सार्थकता है। आज का विद्यार्थी बचपन से ही एक ऐसी अंधी एवं प्रतिस्पर्धी दौड़ में धकेल दिया जाता है, जिसमें लक्ष्य अंक, ग्रेड, और रैंक बन गए हैं-ज्ञान, संवेदना और चरित्र नहीं। स्कूल अब शिक्षालय नहीं, बल्कि परीक्षा-केंद्र यानी गलाकाट प्रतियोगिता के केन्द्र बन चुके हैं। माता-पिता, शिक्षक और समाज-सभी ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है, जहाँ 'सफलता' का अर्थ केवल डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या उच्च वेतन वाली नौकरी तक सीमित हो गया है।

शिक्षा अब व्यक्ति के भीतर के मनुष्यत्व, रचनात्मकता और संवेदना को विकसित करने का माध्यम नहीं रही, बल्कि उसने जीवन को 'प्रदर्शन की प्रतियोगिता' बना दिया है। छोटे बच्चों पर कोचिंग का बोझ, अभिभावकों की अपेक्षाएँ, और असफलता का भय?-ये तीन त्रिकोणीय दबाव उन्हें धीरे-धीरे मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। शिक्षा अब एक बोझ और मानसिक तनाव का कारण बन गयी है।

भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर समय-समय पर प्रश्न खड़े होते रहे हैं। शिक्षा की विसंगतियों एवं दबावों के चलते भी अनेक सवाल खड़े हैं। इन्हीं से जुड़ा यह एक बेहद हृदय विदारक और चिंताजनक तथ्य है कि एक वर्ष में लगभग 14,000 स्कूली बच्चों ने आत्महत्या कर ली। इस तथ्य की पुष्टि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भी

कर रही है। अधिक घातक तथ्य यह है कि बीते एक दशक में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 की तुलना में यह संख्या 34 प्रतिशत अधिक है। यह केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन मासूम सपनों की समाधियाँ हैं जिन्हें हमारी शिक्षा प्रणाली ने दम तोड़ने पर विवश कर दिया। यह स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हुए किसी एक स्कूल, राज्य या केन्द्रसरकार के लिये ही नहीं, बल्कि आमजन के लिये विमर्श का विषय बनना चाहिए।

भारत की शिक्षा केवल बौद्धिक नहीं बल्कि समग्र विकास का माध्यम होनी चाहिए। प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा में विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास पर समान बल दिया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं बल्कि आत्म-ज्ञान, आत्म-नियंत्रण और समाज सेवा की भावना जगाना होता था। आज फिर उसी संतुलित दृष्टि की आवश्यकता है। भावात्मक शिक्षा का अर्थ है संवेदनशीलता का विकास। एक विद्यार्थी जब दूसरे के दुःख को महसूस करना सीखता है तभी वह सच्चा नागरिक बनता है। मानसिक शिक्षा का अर्थ है एकाग्रता, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को संकटों में भी स्थिर रखती है। बौद्धिक शिक्षा तर्क, विवेक और सृजनशीलता का विकास करती है।

शारीरिक शिक्षा स्वस्थ तन के बिना स्वस्थ मन संभव नहीं होने का बोध कराती है, योग, खेल और व्यायाम को शिक्षा का अभिन्न भाग बनाना चाहिए। शैक्षणिक शिक्षा में ज्ञान और व्यावसायिक दक्षता दोनों का समन्वय होना चाहिए ताकि विद्यार्थी जीवनोपयोगी कौशल प्राप्त कर सके। इन सभी पक्षों का समन्वय ही सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति कहलाता है।

भारत की शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो परंपरा और आधुनिकता का संगम बने। गांधीजी ने कहा था कि 'शिक्षा का मतलब है शरीर, मन और आत्मा का समान विकास।' यही भारत की शिक्षा की आत्मा है। हमारी शिक्षा जीवन-केंद्रित हो, केवल नौकरी-केंद्रित नहीं। वह मूल्य-आधारित हो ताकि समाज में नैतिकता और मानवता बनी रहे। उसमें स्थानीय और वैश्विक दृष्टि का संगम हो ताकि विद्यार्थी अपनी जड़ों से जुड़ा रहे पर विश्व की नवीनतम तकनीक से भी परिचित

हो। उसमें अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन मिले ताकि भारत 'ज्ञान अर्थव्यवस्था' का नेतृत्व कर सके। वह समानता और समावेशिता को आधार बनाए चाहे वह भाषा, लिंग या वर्ग के स्तर पर क्यों न हो।

कोई भी शिक्षा प्रणाली उतनी ही सशक्त होती है जितना सशक्त उसका शिक्षक होता है। शिक्षक केवल पढ़ाने वाला नहीं बल्कि प्रेरक, निमार्ता और मार्गदर्शक होता है। आज आवश्यकता है कि शिक्षकों को उचित सम्मान, प्रशिक्षण और आत्मसंतोष मिले। मौलाना आजाद ने कहा था कि 'अच्छे शिक्षक ही राष्ट्र की आत्मा हैं।' शिक्षक को तकनीकी दक्षता के साथ-साथ भावनात्मक और नैतिक दृष्टि से भी सशक्त बनाना होगा। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा में कई सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया है। 5$3$3$4 संरचना, मातृभाषा में शिक्षा, कौशल विकास और बहुविषयी अध्ययन जैसी अवधारणाएं स्वागतयोग्य हैं। लेकिन इन सुधारों का वास्तविक प्रभाव तभी पड़ेगा जब इन्हें जमीनी स्तर पर संवेदनशीलता और समर्पण से लागू किया जाए। भारत की शिक्षा का लक्ष्य केवल डिग्रियां बांटना नहीं बल्कि विश्व को नैतिकता और आध्यात्मिकता की दिशा देना होना चाहिए। हमारे यहां शिक्षा का अर्थ रहा है- 'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात जो मुक्ति दे वही सच्ची विद्या है। आज शिक्षा का अर्थ हो गया है- 'सा विद्या या नियुक्तये' यानी जो नौकरी दे चही सच्ची शिक्षा है। भारत यदि अपनी शिक्षा में विज्ञान के साथ विवेक, तकनीक के साथ नैतिकता और प्रतिस्पर्धा के साथ करुणा को जोड़ दे तो वह विश्व का मार्गदर्शक बन सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा केवल आर्थिक विकास का नहीं बल्कि संस्कृति, चरित्र और चेतना के निर्माण का माध्यम है। मौलाना आजाद के स्वप्न के अनुरूप यदि भारत की शिक्षा नीति में समानता, गुणवत्ता, मूल्य और आत्मा का समन्वय हो सके तो यह राष्ट्र फिर से 'विश्वगुरु' बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। शिक्षा का लक्ष्य केवल यह नहीं कि हम क्या बनें बल्कि यह भी कि हम किसके लिए बनें। शिक्षा यदि मनुष्य को संवेदनशील, आत्मनिष्ठ और समाजोपयोगी बना दे तो वही मौलाना आजाद की सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण पर पाकिस्तान की बौखलाहट

राष्ट्र समाज

पाकिस्तान की भारत-निंदा की आदत कोई नई नहीं है; यह उसकी कूटनीति एवं संकीर्ण सोच का स्थायी चरित्र बन चुकी है। ऐसा शायद ही कोई अवसर हो जब भारत की बढ़ती शक्ति, बढ़ती साख और सांस्कृतिक उन्नयन का प्रभावी दृश्य उभरे और पाकिस्तान उसमें संकुचित मानसिकता से भरी त्रासद टिप्पणियां न करे, विरोध का वातावरण न बनाए या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अनर्गल आरोपों का पुलिंदा न खोले। हाल ही में अयोध्याजी में श्रीराम मंदिर पर हुए ध्वजारोहण समारोह को लेकर उसकी बौखलाहट इसी मानसिक दिवालियापन का ताजा उदाहरण है। भारतीयता के स्वाभाविक सद्भाव में सेंध लगाने का कोई अवसर पाकिस्तान हाथ से नहीं जाने देता। यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, सभ्यता-स्मृति व सांस्कृतिक स्वाभिमान का वह क्षण था जिसने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। पाकिस्तान ने इस ऐतिहासिक घटना का विरोध ही नहीं किया बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र तक ले जाकर शिकायत की, जैसे उसे भारत के हर आंतरिक मामले में बाधा डालना ही अपनी कूटनीतिक जिम्मेदारी समझ में आता हो। इससे पहले भी उसने राम मंदिर निर्माण के अवसर पर अनर्गल विरोध दर्ज कराया था। यह उसका वह ढर्रा है जो भारत के सांस्कृतिक उत्थान एवं उन्नयन की किसी भी झलक को देखकर सहन नहीं कर पाता।

पूरे कुतर्क एवं कुचेष्टाओं के साथ अपने बयान में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने आरोप लगाया है कि श्रीराम मंदिर का ध्वजारोहण भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने की व्यापक प्रवृत्ति का परिणाम है। वैसे, दुनिया जानती है कि किस

देश में अल्पसंख्यक ज्यादा दबाव में हैं। आज के समय में पाकिस्तान में बमुश्किल 50 लाख हिंदू बचे हैं, अन्य अल्पसंख्यक सिख और ईसाई तो न के बराबर हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में बंटवारे से पहले करीब 15 प्रतिशत हिंदू रहा करते थे, पर बंटवारे के बाद हिंदुओं की संख्या 2 प्रतिशत के आस पास आ सिमटी। दूसरी ओर, भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं, इनकी संख्या अन्य अल्पसंख्यकों के साथ तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान की ओर से यह फिजूल टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब पाकिस्तान खुद लंबे समय से हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदिया मुसलमानों सहित दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का केंद्र बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में पूरे पाकिस्तान में ईसाइयों और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा व उत्पीड़न जारी रहा है।

सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली कहावत के अनुसार पाकिस्तान की यह दखलअंदाजी केवल अस्वीकार्य ही नहीं, बल्कि उसकी दोहरी मानसिकता और पाखंडी चरित्र को भी उजागर करती है। विडंबना यह है कि जो देश स्वयं अपने ही नागरिकों को सुरक्षित रखने में असमर्थ है, जो अपने ही अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता रहा है, वह भारत में मुसलमानों के अधिकारों की चिंता में रातभर जागने का अभिनय कर रहा है। वह देश, जहां हिंदुओं की आबादी 1947 से लेकर आज तक लगभग समाप्त होने की कगार पर पहुँच चुकी है, जहां सिखों पर अत्याचार के अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं, जहां ईसाइयों की प्रार्थना सभाओं को अक्सर हिंसा का निशाना बनाया जाता है, वह भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों पर प्रवचन देने का नैतिक अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता है? पाकिस्तान की विश्वसनीयता इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि उसकी हर शिकायत एक राजनीतिक नौटंकी से अधिक कुछ नहीं रह जाती। पाकिस्तान के इस व्यवहार के पीछे भारत के बढ़ते आत्मविश्वास, उभरती वैश्विक प्रतिष्ठा और मजबूत होती राष्ट्र-चेतना का भय साफ दिखाई देता है। भारत आज जिस तेजी से विश्व राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है, उसकी आर्थिक शक्ति जितनी तेजी से बढ़ रही है और जिसके सांस्कृतिक और सभ्यतागत विमर्शों को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिल रहा है, वह पाकिस्तान की बेचैनी का मूल कारण है।

पाकिस्तान यह समझ चुका है कि भारत केवल राजनीतिक या आर्थिक शक्ति के रूप में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में भी उभर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्निर्माण और इसके साथ जुड़ी सांस्कृतिक चेतना भारतीय समाज के भीतर एक नई एकता, नई ऊर्जा और एक नए आत्मसम्मान का निर्माण कर रही है। यही वह शक्ति है जिसे पाकिस्तान सबसे अधिक डरता है क्योंकि एक आत्मविश्वासी, एकजुट और संस्कृति-प्राण भारत उसकी कट्टरपंथी राजनीति और भारत-विरोधी साजिशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान की ओर से जो 'बुकलेट्स' और 'शिकायतें' अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पेश की जाती हैं, वे वस्तुतः उसकी असफल विदेश नीति का प्रमाण-पत्र हैं।

उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर...

राष्ट्र समाज

महाकालेश्वर मंदिर के रहस्यों में दक्षिणमुखी शिवलिंग (जो मृत्यु के देवता यमराज की दिशा में है), महाकाल का उज्जैन का राजा होना (जिस कारण कोई शासक रात नहीं रुकता), स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का होना, और ग्रहण के दौरान भी कपाट न बंद होना शामिल हैं, साथ ही यहां की भस्मारती और नागचंद्रेश्वर मंदिर (जो साल में एक बार खुलता है)भी अद्वितीय हैं, और यह मंदिर प्राचीन काल में विश्व का मानक समय निर्धारण का केंद्र भी था।

महाकाल मंदिर के प्रमुख रहस्य और विशेषताएं:

दक्षिणमुखी शिवलिंग: सभी ज्योतिर्लिंगों में महाकाल ही एकमात्र शिवलिंग हैं जो दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, जिसे मृत्यु की दिशा भी माना जाता है, इसलिए इन्हें दक्षिणमुखी महाकाल कहते हैं।

उज्जैन के राजा: मान्यता है कि महाकाल स्वयं उज्जैन के राजा हैं, इसलिए कोई भी शासक या प्रधानमंत्री रात में उज्जैन में नहीं रुकते, ऐसा करने वालों पर संकट आया है।

काल का केंद्र: प्राचीन काल में महाकालेश्वर मंदिर से ही पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, क्योंकि यह

समय और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं।

स्वयंभू ज्योतिर्लिंग: यह ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है, और यह शक्ति की धाराएं उत्पन्न करता है, जिससे यह अत्यंत शक्तिशाली है।

भस्मारती: बाबा महाकाल का श्रृंगार प्रतिदिन भांग, भस्म (राख), ड्राई फ्रूट्स, चंदन और फूलों से किया जाता है, जिसमें हर दिन अलग-अलग श्रृंगार होता है।

ग्रहण के दौरान कपाट: अन्य मंदिरों के विपरीत, ग्रहण के दौरान भी महाकाल मंदिर के कपाट बंद नहीं होते, क्योंकि महाकाल स्वयं काल के स्वामी हैं।

नागचंद्रेश्वर मंदिर: मंदिर के ऊपरी तल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है,जो केवल नाग पंचमी के दिन साल में एक बार खुलता है, जहां शिव परिवार नाग के फन पर विराजमान हैं।

जूना महाकाल: मुगल काल में शिवलिंग को बचाने के लिए पुजारियों ने असली शिवलिंग को छुपाकर दूसरा शिवलिंग स्थापित किया था, जो अब जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है।

कालभैरव मंदिर: मंदिर के पास ही कालभैरव का मंदिर है, जहां भगवान को मदिरा चढ़ाई जाती है, और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां यह प्रथा है। ये रहस्य महाकालेश्वर मंदिर को एक अद्वितीय और चमत्कारी स्थान बनाते हैं, जहां करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। महाकाल के दर्शन से भक्तों को अकाल मृत्यु से मुक्ति, मोक्ष, भय मुक्ति,धन-धान्य, निरोगी काया और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जो यमराज पर नियंत्रण रखते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता लाते हैं, विशेषकर भस्मारती के दर्शन से पूर्ण कृपा प्राप्त होती है।

विशेष लाभ (भस्मारती): ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली भस्मारती में बाबा के निराकार स्वरूप के दर्शन से मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है और जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। संक्षेप में, महाकाल के दर्शन जीवन के सभी कष्टों को दूर कर आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक सुख प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन सफल व सार्थक बनता है।

महिला खिलाड़ी बेमिसाल रोशन लड़कियां

राष्ट्र समाज

भारतीय खेल जगत में इस दौर को नारी शक्ति के उत्थान का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। यह दबदबा किसी नीतिगत सुधार या अचानक मिले अवसर का परिणाम नहीं है, बल्कि दशकों के संघर्ष, दृढ़ संकल्प और अटूट आत्मविश्वास की उपज है। बीते कुछ समय में महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने यह दशार्या है कि भारतीय खेल परिदृश्य में अब उनका प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप में ऐतिहासिक जीत हो या इसी वर्ष भारतीय महिला कबड्डी टीम का विश्व कप खिताब अपने नाम करना; हर जीत ने देश को नई ऊंचाईयां दी है। लेकिन इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा हासिल है, पहली ब्लाइंड टी20 विश्व कप में भारतीय टीम की खिताबी जीत। यह जीत उन सभी भारतीय महिला खिलाड़ियों के साहस और लगन का प्रतीक है, जो यह साबित करती है कि शारीरिक या सामाजिक बाधाएं सपनों और दृढ़ संकल्प के आगे छोटी पड़ जाती हैं।

यह फतह केवल क्रिकेट के मैदान में ही नहीं, बल्कि दृढ़ इरादों के बल पर किस्मत को बदलने की कहानी है। पहले ब्लाइंड टी20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम की जीत महज एक टूर्नामेंट की जीत नहीं थी, यह जीत हर उस चुनौती पर है, हर उस बंधन पर, जो समाज या नियति ने उन पर लड़कियों पर थोपा है। इन खिलाड़ियों ने साबित किया कि आंखों की रोशनी भले ही कम हो, लेकिन भीतर की इच्छाशक्ति का तेज प्रकाश पूरी दुनिया को देखने और जीतने के लिए काफी होती है। यह जीत अटल इरादे के आगे, शारीरिक बाधा के हारने और ताकत को केवल शारीरिक बल में नापने को झुठलाती है।

पहला दृष्टिबाधित विश्व कप भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रभुत्व का गवाह बना। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद टीम इंडिया ने फाइनल में नेपाल को शिकस्त दी। भारतीय टीम ने इस मैच में अपने संयम और आक्रामकता का अद्भुत प्रदर्शन किया। टीम गेम ने शानदार जीत हासिल की और विश्व विजेता का खिताब अपने नाम किया। यह सफलता भारतीय खेल इतिहास का इसलिए भी स्वर्णिम अध्याय क्योंकि पहली बार दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को विश्व मंच पर क्षमता साबित करने का अवसर मिला। इन खिलाड़ियों ने दोहरी लड़ाई लड़ी। पहली शारीरिक चुनौतियों से और दूसरी आर्थिक और सामाजिक रूढ़ियों से। इनके बावजूद, लड़कियों ने हार नहीं मानी और मैदान में अपनी

पूरी ताकत झोंक दी।

कठिन सफर

दृष्टिबाधित टीम की खिलाड़ियों का सफर अभावों और मुश्किलों से भरा रहा। ये बेटियां देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों से आई हैं, जहां बुनियादी संसाधनों की कमी कठोर सच्चाई है। इस टीम का नेतृत्व दीपिका टीसी ने किया, जो कर्नाटक की हैं। एक दुर्घटना में बचपन में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। खेतीहर परिवार की दीपिका को खुद भी नहीं पता नहीं था कि क्रिकेट उनके जीवन की दिशा तय करेगा। दृष्टिबाधित बच्चों के स्कूल में उन्हें क्रिकेट के बारे में पता चला। शुरूआत में उन्हें यह खेल खेलने में हिचकिचाहट थी। लेकिन उनके शिक्षक ने उन्हें इस खेल में आने के लिए प्रेरित किया। दीपिका कहती हैं कि समय के साथ क्रिकेट ने उन्हें रास्ता सुझाया और आत्मविश्वास दिया। विश्व कप में देश का नेतृत्व करना अब तक के उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि है। उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य जेमिमा रोड्रिग्स और पुरुष टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का भी समर्थन मिला। जेमिमा हाल ही में हुए महिला विश्व कप टीम का हिस्सा थीं, जिसने खिताब जीता है।

दृष्टिबाधित टीम की उप-कप्तान, महाराष्ट्र की गंगा कदम, नौ भाई-बहनों के परिवार से आई हैं। उनके किसान पिता ने उन्हें स्थिर भविष्य देने के लिए दृष्टिबाधित स्कूल में भर्ती कराया था। स्कूल में वे शौकिया क्रिकेट खेलती थीं। लेकिन उनके शिक्षक ने उन्हें इस खेल को गंभीरता से खेलने के लिए प्रेरित किया। गंगा के लिए ध्वनि की दिशा में समय रहते बॉल फेंकना या बैटिंग करना सीखना बड़ी चुनौती थी। 26 वर्षीय गंगा ने इसे सीखने के लिए बड़ी लगन से मेहनत की। आज वे अपने गांव की दूसरी दृष्टिबाधित लड़कियों को खेलने के लिए प्रेरित करती हैं। जम्मू-कश्मीर की रहने वाली, शीर्ष क्रम की बल्लेबाज अनेखा देवी 20 साल की हैं। जन्म से ही उनकी आंखों में आंशिक रोशनी है। उनके चाचा भी दृष्टिबाधित हैं। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने ही अनेखा को दिल्ली में दृष्टिबाधित क्रिकेट शिविर में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

ओडिशा के आदिवासी समुदाय से आने वाली 18 साल की ऑलराउंडर, फूला सरेन ने पांच साल की उम्र में अपनी बाईं आंख की रोशनी खो दी। इसी उम्र में उनकी मां भी चल बसीं। दृष्टिबाधित स्कूल की एक शिक्षिका ने उन्हें क्रिकेट के बारे में बताया। वहां से टूर्नामेंट तक की उनकी यात्रा बहुत चुनौतीपूर्ण थी। क्रिकेट सीखने के साथ परिवार को समझाना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके लिए जीवन में ट्रॉफी से ज्यादा यह मायने रखता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अपनी पहचान है। मध्य प्रदेश की सुनीता सारथे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बस अंतर यह है कि वे स्कूल के बाद कॉलेज गईं, वहां अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर कई जगह नौकरी की तलाश की। फिर उनके एक दोस्त ने उन्हें दृष्टिबाधित क्रिकेट के बारे में बताया। वे शिविर में शामिल हुईं। शुरूआत में उन्हें यह खेल तेज और जटिल लगा लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके कोच बताते हैं कि सुनीता अतिरिक्त मेहनत करती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने देर से शुरूआत की है। अब वे भारत की सबसे भरोसेमंद फील्डरों में एक हैं।

शादी के जोड़े में दिखे रश्मिका- विजय! गुपचुप की शादी

एक्टर रश्मिका मंदाना व विजय देवरकोंडा एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। हाल ही में दोनों की कुछ शादी जैसी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं, जिन्हें देखकर फैंस को लगा कि शायद इस कपल ने गुपचुप शादी कर ली है। हालांकि, इस वायरल खबर के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें एआई तकनीक से बनाई गई नकली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम यूजर गुंटी श्रीकला नागराजू ने शेयर किया था। फोटो में रश्मिका और विजय शादी के कपड़ों में नजर आ रहे हैं, गले में वरमाला पहने हुए। तस्वीरों में उनके साथ महेश बाबू और उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर भी दिखाई दे रहे हैं। पीछे फूलों की सजावट के साथ विजय और रश्मिका ' लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग धोखा खा गए। हाल ही में हैदराबाद में रश्मिका की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' की सक्सेस पार्टी के दौरान दोनों के बीच खास बॉन्डिंग देखने को मिली। इस मौके पर विजय ने मंच पर रश्मिका का हाथ थामा और प्यार से उसे किस किया। यह नजारा देखकर फैंस काफी खुश हो गए और रश्मिका भी शरमाती हुई नजर आईं। रश्मिका अपनी फिल्म 'थामाट के प्रमोशनल इवेंट में भी सुर्खियों में रहीं। जब उनसे उनकी सगाई को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा- 'इसके बारे में तो सब जानते हैं।' उनके इस जवाब से साफ हो गया कि दोनों अपनी सगाई को लेकर खुश हैं। वहीं, विजय की टीम ने भी बताया है कि दोनों अगले साल शादी करेंगे।कुछ समय पहले रश्मिका ने सोशल मीडिया पर अपने पालतू डॉग ऑरा के साथ एक वीडियो शेयर किया था।

आंटी कहने पर अर्चना को होने वाली बहू पर आया गुस्सा

अर्चना पूरन सिंह ने अपने फैमिली व्लॉग आप का परिवार की पहली सालगिरह मनाई। इस व्लॉग की शुरूआत उन्होंने एक साल पहले पति परमीत सेठी और दोनों बेटों आर्यमन और आयुष्मान के साथ की थी। तब से यह परिवार अपने मजेदार और सच्चे पलों को व्लॉग के जरिए लोगों के साथ शेयर करता आ रहा है। पहली एनिवर्सरी को खास बनाने के लिए अर्चना और उनके परिवार ने घर में ही एक छोटा-सा अवॉर्ड फंक्शन रखा। इसमें उन सभी लोगों को अवॉर्ड दिए गए, जो पिछले एक साल में उनके व्लॉग का हिस्सा बने। इसी दौरान एक मजेदार किस्सा भी देखने को मिला। आर्यमन की मंगेतर और अर्चना की होने वाली बहू योगिता बिहानी ने होस्ट किया। घर को रेड कार्पेट की तरह सजाया गया था और सभी लोग तय ड्रेस कोड में आए थे। लेकिन जब आर्यमन की एंट्री हुई, तो उन्होंने ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया। इस पर योगिता ने मजाक में उनकी हल्की-फुल्की टांग खिंचाई कर दी, जिसे सबने हंसी-मजाक में लिया। जब अवॉर्ड्स देने की बारी आई तो योगिता ने अर्चना पूरन सिंह को 'आंटी' कहकर बुला लिया। यह बात अर्चना को अच्छी नहीं लगी।

दीपिका का ऐसा रोमांस पहले कभी नहीं देखा होगा!

सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'किंग' को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। साल 2026 में रिलीज होने वाली यह फिल्म पहले से ही सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में गिनी जा रही है। इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।फिल्म का पहला लुक इस साल शाहरुख खान के जन्मदिन पर सामने आया था, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इसी बीच अब एक नया वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसमें शाहरुख और दीपिका को रोमांटिक अंदाज में दिखाया गया है।

वीडियो के बैकग्राउंड में 'मैं तो बहक गया' नाम का गाना सुनाई दे रहा है, जिससे लोगों को लगा कि यह फिल्म 'किंग' का कोई लीक सॉन्ग है। हालांकि, बाद में यह साफ हो गया कि यह वीडियो फिल्म से जुड़ा असली कंटेंट नहीं है, बल्कि ए आई तकनीक से तैयार किया गया एक एडिटेड क्लिप है। शुरूआत में इसे एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया गया था, जहां दावा किया गया कि यह फिल्म का लीक वीडियो है। लेकिन जल्द ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी सच्चाई उजागर कर दी।

सारा अर्जुन को किस करने पर बुरे फंसे राकेश बेदी

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों दर्शकों और बॉक्स ऑफिस दोनों पर छाई हुई है। फिल्म ने रिलीज के बाद से ही शानदार कमाई की है और लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। रिलीज के 14वें दिन फिल्म ने 23 करोड़ रुपये का बिजनेस किया, जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन 450 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस सफलता के साथ 'धुरंधर' साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई है।

फिल्म में सभी कलाकारों के एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन को लेकर है। ट्रेलर सामने आने के बाद से ही रणवीर सिंह के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन रोमांटिक केमिस्ट्री दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म में सारा, सीनियर एक्टर राकेश बेदी की बेटी का किरदार निभा रही हैं।

हाल ही में फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान सारा अर्जुन और राकेश बेदी से जुड़ा एक पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस दौरान राकेश बेदी द्वारा सारा को किस करने पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने आपत्ति जताई और इसे गलत नजरिए से देखा गया। इसके बाद अभिनेता को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस पूरे मामले पर राकेश बेदी ने अब अपनी सफाई दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को बेवजह बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सारा उनके लिए बेटी जैसी हैं और फिल्म की शूटिंग के दौरान भी उनके बीच बिल्कुल बाप-बेटी जैसा रिश्ता रहा है।

खेसारी-आम्रपाली के रोमांस ने छुड़ाया फैन्स का पसीना

खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के एक धुरंधर कलाकार हैं। उनके अंदाज और आवाज के तो लोग दीवाने हैं। उनका जो भी गाना रिलीज होता है वह आते ही इंटरनेट पर छा जाता है। खेसारी लाल यादव इतने बड़े एक्टर हैं कि उनके नए के साथ ही पुराने वीडियो भी इंटरनेट पर छाए रहते हैं। बता दें कि हाल ही में खेसारी लाल यादव का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव का एक तीन साल पुराना गाना इंटरनेट पर बुलेट की रफ्तार से भाग रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव आम्रपाली दुबे के साथ इतना रोमांटिक डांस करते हैं कि लोग खेसारी के दीवाने हो जाते हैं। बता दें कि दोनों के इस गाने का नाम है 'हरियकी ओढ़निया' इस गाने में खेसारी और आम्रपाली की केमिस्ट्री फैन्स के पसीने छुड़ा दे रही है। दोनों का यह गाना इंटरनेट संसेशन बन गया है। बता दें कि दोनों का यह गाना फिल्म 'डोली सजा के रखना' का है। इस गाने के लिरिक्स विजय चौहान ने लिखे हैं और इस गाने में म्यूजिक आर्या शर्मा ने दिया है। इस गाने को निर्देश रजनीश मिश्रा ने किया है। दोनों का यह गाना साल 2022 में एसआरके म्यूजिक नाम के यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है। दोनों के इस गाने पर अभी तक 100 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। इन व्यूज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैन्स को दोनों का यह गाना कितना पंसद आया है।

भोजपुरी फिल्म 'रंग दे बसंती' ने की थी छप्परफाड़ कमाई

हाई बजट की फिल्मों में आपने हमेशा बॉलीवुड और साउथ सिनेमा को टक्कर देते देखा होगा, बॉलीवुड की फिल्में तो हाई बजट ही रहती हैं जैसे की 300 से 400 करोड़ के आसपास। इन फिल्मों की कमाई भी लगभग 1000 करोड़ से ऊपर ही जाती है। हाल ही में फिल्म धुरंधर रिलीज हुई है जो रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है। वहीं भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो इन फिल्मों का बजट इतना नहीं रहता है। कई फिल्में ऐसी हैं जो कम बजट में बनती हैं तगड़ी कमाई करती हैं। चलिए जानते हैं इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म में खेसारी लाल आपको लीड रोल में नजर आ रहे हैं। वहीं उनके साथ उनके बेटे ऋषभ भी अहम भूमिका में खेसारी का साथ देते दिख रहे हैं।

नया बीमा कानून ऐसे बदलेगा आपकी पॉलिसी?

संसद में हाल ही में पारित 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक 2025' को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बीमा क्षेत्र के लिए बड़ा सुधार बताया है। एलआईसी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक आर. दुरईस्वामी ने कहा कि यह विधेयक बीमा उद्योग के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा और पॉलिसियों को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाएगा। दुरईस्वामी ने जारी बयान में कहा कि नया कानून पॉलिसीधारकों की सुरक्षा, मजबूत नियमन और बेहतर शासन व्यवस्था पर विशेष जोर देता है। उनके मुताबिक, पुरानी व्यवस्थाओं को अपडेट कर और गवर्नेंस मानकों को सख्त बनाकर बीमा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी को मजबूत किया गया है।

बता दें कि संसद ने यह विधेयक पारित किया, जिससे बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का रास्ता साफ हो गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशभर में बीमा की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया था। एलआईसी प्रमुख ने कहा कि यह नया ढांचा बीमाकताओं को अधिक परिचालन स्वतंत्रता और नवाचार की सुविधा देगा। इसके तहत सेवानिवृत्ति सुरक्षा, दीघार्यु समाधान और स्वास्थ्य बीमा जैसी बदलती जरूरतों के अनुसार नए और लक्षित उत्पाद विकसित किए जा सकेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि संशोधित कानून के तहत भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की भूमिका और मजबूत होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ-साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। दुरईस्वामी के अनुसार, इन सुधारों से एलआईसी को अपनी पहुंच और मजबूत करने, तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने और सार्वभौमिक बीमा कवरेज के राष्ट्रीय लक्ष्य में अहम योगदान देने में मदद मिलेगी।

आरईसी लिमिटेड का एमईपीडीसीएल, सीपीआरआई के बीच ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन

आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और अग्रणी एनबीएफसी, ने मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमईपीडीसीएल) और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) की सफलतापूर्वक मध्यस्थता की है। एमईपीडीसीएल और

सीपीआरआई द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मेघालय के मुख्य सचिव डॉ. शकील पी. अहमद, आरईसी के सीएमडी जितेंद्र श्रीवास्तव, सीपीआरआई की महानिदेशक डॉ. जे. श्रीदेवी, आरईसी के ईडी प्रिंस धवन, आरईसी के सीपीएम गुवाहाटी शुभेंदु रॉय व एमईपीडीसीएल, सीपीआरआई और आरईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए। यह रणनीतिक साझेदारी मेघालय और पूरे पूर्वोत्तर भारत में, विशेष रूप से प्रमुख पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत, बिजली वितरण बुनियादी ढांचे के लिए गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एनएबीएल मान्यता लक्ष्यः समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य मेघालय में एक एनएबीएल-मान्यता प्राप्त परीक्षण सुविधा स्थापित करना है, जो दूरस्थ प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता परीक्षण के लिए सामग्री भेजने में उत्तर पूर्वी राज्यों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण रसद चुनौतियों और देरी का समाधान करेगी।

सीपीआरआई का तकनीकी नेतृत्वः विद्युत क्षेत्र का एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन, सीपीआरआई, व्यापक परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसमें खरीद के लिए विस्तृत विनिर्देश तैयार करना, दस्तावेजीकरण का मार्गदर्शन करना और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी सहायता प्रदान करना शामिल है कि एमईपीडीसीएल की सुविधा एनएबीएल निरीक्षण के लिए पूरी तरह से सुसज्जित और तैयार है। आरईसी लिमिटेड की मध्यस्थता और सहायताः आरडीएसएस के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, आरईसी लिमिटेड ने इस समझौते की मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सख्त गुणवत्ता नियंत्रण और योजना परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई। एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की स्थानीय उपलब्धता से फील्ड मैटेरियल क्वालिटी टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन (एफएमक्यूआई) प्रक्रिया में उल्लेखनीय तेजी आने की उम्मीद है, जो पहले लंबी दूरी तक वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) जैसे भारी उपकरणों के परिवहन की आवश्यकता के कारण विलंबित हो जाती थी। स्थानीय क्षमता में वृद्धिः एमईपीडीसीएल आवश्यक परीक्षण उपकरण (एचवी परीक्षण बेंच और आवृत्ति मीटर जैसे विशिष्ट उपकरणों सहित) उपलब्ध कराएगा, मौजूदा परिसंपत्तियों का अंशांकन करेगा और सुविधा तैयार करेगा।

।।श्री गणेशाय नम।।

आमंत्रण पत्र

पं. मदनमोहन मालवीय जी

एवं

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी

के जन्मोत्सव पर

विचार गोष्ठी

एवं

महामना सम्मान

25, DEC.-2025

दिनांक : गुरुवार 25 दिसम्बर 2025

साम्य : 2:00 Pm to 5:00 Pm

स्थान : कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

: मुख्य प्रायोजक :

ओएनजीसी ONGC

: प्रायोजक :

गेल GAIL | LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA | NAFED | सकरनी | BTW | LOHIA | GOOD MORNING CLUB PASCHIM VIHAR

: मीडिया पार्टनर :

राष्ट्र समाज | राष्ट्र तक | नवोदय टाइम्स | पंजाब केसरी | दिशा

: आयोजक :

Samadhan Foundation

THE POWER TO GO FASTER

ENERGISING INFINITE POSSIBILITIES FOR VIKSIT BHARAT

एनटीपीसी NTPC

50 YEARS OF POWERING GROWTH

For half a century, we've fueled India's race towards success. With hydro, wind, solar, hydrogen, and nuclear joining our thermal strength, we are fueling your unstoppable rise. So that a nation in speed has the power to go faster.

— NTPC'S CAPACITY MIX —

THERMAL | HYDRO | WIND | SOLAR | PSP | GREEN HYDROGEN | NUCLEAR

ntpc.co.in

RNI No.: DELHIN/2014/56304